Dainik Jagran, Delhi, 20/02/2026
Page No: 2, Size: 50.91cm × 15.35cm

एनएचआरसी ने नाम और लोगो के दुरुपयोग पर सभी राज्यों को भेजा नोटिस

- दिल्ली में इसी नाम से एक एनजीओ के पंजीकृत पाए जाने पर आयोग ने लिया संज्ञान
- संगठन के विजिटिंग कार्ड पर प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदनाम दर्ज थे, जिसे आयोग ने भ्रामक कहा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने नाम और लोगो का दुरुपयोग करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि उसके नाम से मिलते-जुलते भ्रामक संगठनों की गतिविधियां जारी रहना सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है।

हाल ही में आयोग के संज्ञान में नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल (एनएचआरसी) नाम से एक एनजीओ आया, जो वर्ष 2022 में दिल्ली में पंजीकृत हुआ था और अपने प्रचार सामग्री में विभिन्न सरकारी संस्थाओं से संबद्ध होने का दावा कर रहा था। संगठन के विजिटिंग कार्ड पर प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदनाम भी दर्शाए गए, जिसे आयोग ने भ्रामक बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

इसके साथ ही आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर ऐसे संगठनों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने, आवश्यक होने पर उनका पंजीकरण रद करने और संबंधित पंजीकरण प्राधिकरणों को सतर्क करने का निर्देश दिया है। एनएचआरसी ने पाया कि कई एनजीओ स्वयं को ऐसे नामों से पंजीकृत करा रहे हैं जो आयोग के नाम से बेहद मिलते-जुलते हैं, जिससे आम जनता और सरकारी एजेंसियों में भ्रम पैदा होता है। आयोग के अनुसार इससे उसके अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग, फंड के संभावित दुरुपयोग और संस्थागत विश्वसनीयता पर असर पड़ने का खतरा है।

आयोग ने कहा कि पहले भी संबंधित प्राधिकरणों को ऐसे फर्जी या भ्रामक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगाह किया गया था, लेकिन उल्लंघन जारी रहने के कारण अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

Amar Ujala, Delhi, 20/02/2026
Page No: 13, Size: 4.26cm × 8.28cm

एनजीओ पर एनएचआरसी के नाम व लोगो इस्तेमाल करने का आरोप, नोटिस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कुछ गैर-सरकारी संगठनों के उसके नाम और लोगो के दुरुपयोग का संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को नोटिस जारी कर इन संगठनों के खिलाफ दो हफ्ते में कार्रवाई करने को कहा है। ये एनजीओ भ्रामक रूप से आयोग से मिलते-जुलते नामों से पंजीकृत हैं। आयोग ने कहा कि ऐसे भ्रामक नामों जनादेश के दुरुपयोग, धन के संभावित गबन और सार्वजनिक अधिकारियों के लिए भ्रम पैदा कर सकता है। एजेंसी

Greater Kashmir, Srinagar, 20/02/2026
Page No: 10, Size: 20.16cm × 9.92cm

NHRC takes suo motu cognisance of misuse of its name, logo by NGOs

GK News Service
New Delhi, Feb 19

The National Human Rights Commission (NHRC), has taken suo motu cognizance of the misuse of its name and logo by certain non-governmental organisations registered under deceptively similar titles. While examining complaints relating to alleged human rights violations, the Commission observed that several NGOs across the country have registered themselves under names closely resembling that of the statutory body, creating confusion among the public.

The Commission recently identified an NGO operating under the name "National Human Rights Council (NHRC)", reportedly registered in 2022 with the Government of NCT of Delhi. Its publicity materials allegedly claim registration with NITI Aayog, the Ministry of Corporate Affairs and the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, along with association with other human rights bodies. A visiting card linked to the organisation also carried the designation "State Chairman, Karnataka".

Terming the matter serious, the Commission noted that such nomenclature and use of titles like "Chairman" are misleading and may give the impression that these entities are part of or authorised by the NHRC. It observed that continuation of such illusory names could erode public trust, result in misuse of mandate, possible misappropriation of funds and create confusion for authorities in distinguishing between a statutory body and private organisations.

The NHRC said it had earlier flagged misuse of its name and logo to the concerned authorities and sought strict action, but violations continue to surface. The Commission has now issued notices to the Chief Secretaries and Directors General of Police of all States and Union Territories, directing them to identify NGOs or individuals misusing its name or using deceptively similar titles and to take immediate legal action within two weeks, including cancellation of registrations obtained in violation of norms. Authorities have also been asked to sensitise registering officials to prevent such misuse.

Aaj, Lucknow, 20/02/2026
Page No: 7, Size: 9.74cm × 5.87cm

मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर का आगमन

बहराइच। सहायक श्रमायुक्त सिद्धार्थ मोदियानी ने बताया कि मा. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (बाल एवं बधुआ श्रम) के स्पेशल मॉनिटर धनन्जय टिंगल जनपद बहराइच के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत 19 फरवरी को अपरान्ह में जनपद पहुंचकर लो.नि.वि. बहराइच के निरीक्षण गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। श्री टिंगल 20 फरवरी 2026 को जनपद में बाल एवं बधुआ श्रम से संबंधित अधिनियमों के क्रियान्वयन तथा उक्त से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु पूर्वान्ह 11:00 बजे निरीक्षण भवन में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी तथा संबंधित गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक करेंगे। श्री टिंगल बैठक के उपरान्त अपरान्ह 02:00 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जायेंगे।

Hindustan, Patna, 20/02/2026
Page No: 10, Size: 13.31cm × 9.26cm

मानवाधिकार के नाम और चिह्न का दुरुपयोग करने वाले एनजीओ का पंजीकरण रद्द होगा

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लिया
- राज्यों के मुख्य सचिव-डीजीपी को कानूनी कार्रवाई के दिए निर्देश

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मानवाधिकार के नाम का दुरुपयोग या इससे मिलते-जुलते भ्रामक नामों का उपयोग करने वाले व्यक्ति व संगठनों पर कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी की है।

अधिकारियों को ऐसे व्यक्ति और संगठन की पहचान कर दो सप्ताह के भीतर उन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार ऐसे नाम की संस्थाओं के पंजीयन में भी सतर्कता बरते। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाली इन संस्थाओं का पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई करे। आयोग ने बताया कि कई गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या भ्रामक रूप से मिलते-जुलते नामों से अपना पंजीकरण कराया है। इनके द्वारा आयोग के नाम व चिह्न के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे भ्रामक नामों के सक्रिय रहने से जन विश्वास को ठेस पहुंचेगा ही जनादेश का भी दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे संदिग्ध संगठनों से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद उल्लंघन जारी है। आयोग ने कहा कि सार्वजनिक अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे वैधानिक निकाय और गैर-सरकारी संगठनों के बीच अंतर करने में भ्रम पैदा कर सकता है।

Source: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2230154®=3&lang=2

NHRC, India takes suo motu cognizance of misuse of its name and logo by Non-Governmental Organisations (NGOs) registered under names deceptively similar to it

Notes such violations continuing despite informing the concerned authorities to take strict action against people behind such dubious organisations
Observes that continuation of such illusory names may erode public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds and create confusion for public authorities in distinguishing between a statutory body like NHRC and NGOs
Notices issued to Chief Secretaries and DGPs of all States/ UTs to take action within two weeks

Additionally, further reports sought from Karnataka Chief Secretary and DGP as well as Delhi Chief Secretary and Commissioner of Police on the matter of an NGO registered as “National Human Rights Council (NHRC)” using misleading credentials and designations

Posted On: 19 FEB 2026 1:22PM

The National Human Rights Commission (NHRC), India has been receiving complaints from individual complainants as well as Non-Governmental Organisations (NGOs) across the country alleging violation of human rights. While examining these complaints, the Commission has observed that several NGOs have got themselves registered under names deceptively similar to that of the National Human Rights Commission (NHRC).

Recently, the Commission came across an NGO registered as “National Human Rights Council (NHRC)”, reportedly registered with the Government of NCT of Delhi in 2022. Its publicity material claims, “Registered by Govt. of NITI Aayog”, “Registered by Ministry of Corporate Affairs, India”, “Registered under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India” and association with “Andhra Pradesh Human Rights Council Association”. A visiting card apparently related to the said organisation also bears the inscription “Venkatesh, State Chairman, Karnataka”.

Considering the gravity of the matter, it has taken suo motu cognizance of the matter. It has observed that the name adopted and the designation “Chairman” is misleading and creates confusion. Deceptive nomenclature misleads the public into believing that these organisations are either part of the National Human Rights Commission or recognised/ authorised by it to deal with human rights issues.

The Commission is of the view that continuation of such illusory names may erode public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds and create confusion for public authorities in distinguishing between a statutory body like NHRC and NGOs.

The Commission had earlier expressed concern through various platforms regarding the misuse of its name and logo and informed the authorities concerned to take action against the people behind such dubious organisations. However, violations continue to come to its notice.

Therefore, the Commission has issued notices to the Chief Secretaries and Director Generals of Police of all the States/ UTs to identify such NGOs/ individuals misusing the name of the National Human Rights Commission or using names deceptively similar to it and take immediate legal action within two weeks, including cancellation of registrations obtained in violation of norms. They have also been asked to sensitise registering authorities to remain vigilant and take necessary action against defaulters.

Additionally, in the instant matter of National Human Rights Council (NHRC), the Chief Secretary and the Director General of Police, Karnataka and the Chief Secretary and the Commissioner of Police, Delhi have been further

directed to submit reports within two weeks regarding the action taken against the NGO, having its office in Karnataka and registered in Delhi.

***

NSK

(Release ID: 2230154) Visitor Counter : 243

Deccan Chronicle, Online News, 20/02/2026

Source: https://www.deccanchronicle.com/nation/the-nhrc-will-take-action-against-the-misuse-of-its-name-and-logo-1938403

NHRC Flags Misuse of Its Name, Logo

By NGOs PTI 19 February 2026 4:35 PM

NHRC issued notices to authorities in all states and UTs to take action within two weeks.

The NHRC said it has been receiving complaints from individual complainants as well as non-governmental organisations (NGOs) across the country alleging violation of human rights.

New Delhi : The NHRC on Thursday said it has taken cognisance of "misuse of its name and logo" by some NGOs registered under nomenclatures which are "deceptively similar" to it, and issued notices to authorities in all states and UTs to take action within two weeks. The National Human Rights Commission (NHRC), in a statement, observed that continuation of such "illusory names may erode public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds and create confusion for public authorities" in distinguishing between a statutory body like the NHRC and NGOs.

The rights panel said it had earlier expressed concern through various platforms regarding the "misuse of its name and logo" and informed authorities concerned to take action against the people behind such "dubious organisations". However, violations continue to come to its notice, the statement said. The NHRC said it has been receiving complaints from individual complainants as well as non-governmental organisations (NGOs) across the country alleging violation of human rights.

"While examining these complaints, the Commission has observed that several NGOs have got themselves registered under names deceptively similar to that of the National Human Rights Commission (NHRC)," the statement said. Recently, the Commission came across an NGO registered as 'National Human Rights Council (NHRC)', reportedly registered with the government of Delhi in 2022. Its publicity material claims, "Registered by Govt. of NITI Aayog", "Registered by Ministry of Corporate Affairs, India", "Registered under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India" and association with "Andhra Pradesh Human Rights Council Association", the statement said.

A visiting card apparently related to the said organisation also bears the inscription 'Venkatesh, State Chairman, Karnataka,' it said. Considering the gravity of the matter, it has taken suo motu cognisance of the matter. It has observed that the name adopted and the designation 'Chairman' is "misleading and creates confusion", the statement said. "Deceptive nomenclature misleads the public into believing that these organisations are either part of the National Human Rights Commission or recognised/authorised by it to deal with human rights issues," the NHRC flagged. Therefore, the Commission has issued notices to the chief secretaries and director generals of police of all the states and UTs to "identify such NGOs individuals misusing the name of the NHRC or using names deceptively similar to it, and to take immediate legal action within two weeks, including cancellation of registrations obtained in violation of norms," it said.

They have also been asked to sensitise registering authorities to remain vigilant and take necessary action against defaulters. "Additionally, in the instant matter of National Human Rights Council (NHRC), the chief secretary and the director general of police, Karnataka and the chief secretary and the commissioner of police, Delhi have been further directed to submit reports within two weeks regarding the action taken against the NGO, having its office in Karnataka and registered in Delhi," it said.

(Source : PTI)

Source: https://m.greaterkashmir.com/article/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-misuse-of-its-name-logo-by-ngos/480116/amp

NHRC takes suo motu cognisance of misuse of its name, logo by NGOs

A visiting card linked to the organisation also carried the designation “State Chairman, Karnataka”

11:04 PM Feb 19, 2026 IST | GK NEWS SERVICE

New Delhi, Feb 19: The National Human Rights Commission (NHRC), has taken suo motu cognizance of the misuse of its name and logo by certain non-governmental organisations registered under deceptively similar titles. While examining complaints relating to alleged human rights violations, the Commission observed that several NGOs across the country have registered themselves under names closely resembling that of the statutory body, creating confusion among the public.

The Commission recently identified an NGO operating under the name “National Human Rights Council (NHRC)”, reportedly registered in 2022 with the Government of NCT of Delhi. Its publicity materials allegedly claim registration with NITI Aayog, the Ministry of Corporate Affairs and the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, along with association with other human rights bodies. A visiting card linked to the organisation also carried the designation “State Chairman, Karnataka”.

Terming the matter serious, the Commission noted that such nomenclature and use of titles like “Chairman” are misleading and may give the impression that these entities are part of or authorised by the NHRC. It observed that continuation of such illusory names could erode public trust, result in misuse of mandate, possible misappropriation of funds and create confusion for authorities in distinguishing between a statutory body and private organisations.

The NHRC said it had earlier flagged misuse of its name and logo to the concerned authorities and sought strict action, but violations continue to surface. The Commission has now issued notices to the Chief Secretaries and Directors General of Police of all States and Union Territories, directing them to identify NGOs or individuals misusing its name or using deceptively similar titles and to take immediate legal action within two weeks, including cancellation of registrations obtained in violation of norms. Authorities have also been asked to sensitise registering officials to prevent such misuse.

Source: https://telanganatoday.com/nhrc-flags-misuse-of-its-name-and-logo-by-ngos

NHRC flags misuse of its name and logo by NGOs

The National Human Rights Commission has flagged the misuse of its name and logo by NGOs with deceptively similar titles and directed states and UTs to take action within two weeks. It warned that such practices mislead the public and erode trust

By PTI | Published Date - 19 February 2026, 09:46 PM

New Delhi: The National Human Rights Commission on Thursday said it has taken cognisance of the “misuse of its name and logo” by some NGOs registered under nomenclatures which are “deceptively similar” to it, and issued notices to authorities in all states and UTs to take action within two weeks.

The National Human Rights Commission (NHRC), in a statement, observed that the continuation of such “illusory names may erode public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds, and create confusion for public authorities” in distinguishing between a statutory body like the NHRC and NGOs.

The rights panel said it had earlier expressed concern through various platforms regarding the “misuse of its name and logo” and informed the authorities concerned to take action against the people behind such “dubious organisations”.

However, violations continue to come to its notice, the statement said.

The NHRC said it has been receiving complaints from individual complainants as well as non-governmental organisations (NGOs) across the country alleging violation of human rights.

“While examining these complaints, the Commission has observed that several NGOs have got themselves registered under names deceptively similar to that of the National Human Rights Commission (NHRC),” the statement said.

Recently, the Commission came across an NGO registered as ‘National Human Rights Council (NHRC)’, reportedly registered with the government of Delhi in 2022. Its publicity material claims, “Registered by Govt. of NITI Aayog”, “Registered by Ministry of Corporate Affairs, India”, “Registered under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India” and association with “Andhra Pradesh Human Rights Council Association”, the statement said.

A visiting card apparently related to the said organisation also bears the inscription ‘Venkatesh, State Chairman, Karnataka,’ it said.

Considering the gravity of the matter, it has taken suo motu cognisance of the issue.

It has observed that the name adopted and the designation ‘Chairman’ are “misleading and create confusion”, the statement said.

“Deceptive nomenclature misleads the public into believing that these organisations are either part of the National Human Rights Commission or recognised or authorised by it to deal with human rights issues,” the NHRC flagged. Therefore, the Commission has issued notices to the chief secretaries and directors general of police of all the states and UTs to “identify such NGOs and individuals misusing the name of the NHRC or using names deceptively similar to it, and to take immediate legal action within two weeks, including cancellation of registrations obtained in violation of norms,” it said.

They have also been asked to sensitise registering authorities to remain vigilant and take necessary action against defaulters.

“Additionally, in the instant matter of National Human Rights Council (NHRC), the chief secretary and the director general of police, Karnataka, and the chief secretary and the commissioner of police, Delhi, have been further

directed to submit reports within two weeks regarding the action taken against the NGO, having its office in Karnataka and registered in Delhi," it said.

Source: https://www.etvbharat.com/amp/en/bharat/nhrc-flags-misuse-of-its-name-logo-by-ngo-directs-authorities-to-take-action-enn26021904021

NHRC Flags Misuse Of Its Name, Logo By NGOs; Takes Suo Moto Cognizance

NHRC observed continuation of illusory names may weaken public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds and create confusion for public authorities.

By ETV Bharat English Team

Published : February 19, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read

New Delhi:The NHRC on Thursday said it has taken cognisance of "misuse of its name and logo" by some NGOs registered under nomenclatures which are "deceptively similar" to it, and issued notices to authorities in all states and UTs to take action within two weeks.

The National Human Rights Commission (NHRC), in a statement, observed that continuation of such "illusory names may erode public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds and create confusion for public authorities" in distinguishing between a statutory body like the NHRC and NGOs.

The rights panel said it had earlier expressed concern through various platforms regarding the "misuse of its name and logo" and informed authorities concerned to take action against the people behind such "dubious organisations".

However, violations continue to come to its notice, the statement said. The NHRC said it has been receiving complaints from individual complainants as well as non-governmental organisations (NGOs) across the country alleging violation of human rights.

"While examining these complaints, the Commission has observed that several NGOs have got themselves registered under names deceptively similar to that of the National Human Rights Commission (NHRC)," the statement said.

Recently, the Commission came across an NGO registered as 'National Human Rights Council (NHRC)', reportedly registered with the government of Delhi in 2022. Its publicity material claims, “Registered by Govt. of NITI Aayog”, “Registered by Ministry of Corporate Affairs, India”, “Registered under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India” and association with “Andhra Pradesh Human Rights Council Association”, the statement said.

A visiting card apparently related to the said organisation also bears the inscription 'Venkatesh, State Chairman, Karnataka,' it said. Considering the gravity of the matter, it has taken suo motu cognisance of the matter. It has been observed that the name adopted and the designation 'Chairman' is "misleading and creates confusion", the statement said.

"Deceptive nomenclature misleads the public into believing that these organisations are either part of the National Human Rights Commission or recognised/authorised by it to deal with human rights issues," the NHRC flagged.

Therefore, the Commission has issued notices to the chief secretaries and director generals of police of all the states and UTs to "identify such NGOs individuals misusing the name of the NHRC or using names deceptively similar to it, and to take immediate legal action within two weeks, including cancellation of registrations obtained in violation of norms," it said.

They have also been asked to sensitise registering authorities to remain vigilant and take necessary action against defaulters.

"Additionally, in the instant matter of National Human Rights Council (NHRC), the chief secretary and the director

general of police, Karnataka and the chief secretary and the commissioner of police, Delhi have been further directed to submit reports within two weeks regarding the action taken against the NGO, having its office in Karnataka and registered in Delhi," it said.

Source: https://www.millenniumpost.in/amp/nation/nhrc-flags-misuse-of-its-name-logo-by-ngos-648963

NHRC flags misuse of its name, logo by NGOs

By - MPost | Update: 2026-02-19 19:18 GMT

New Delhi: The NHRC on Thursday said it has taken cognisance of "misuse of its name and logo" by some NGOs registered under nomenclatures which are "deceptively similar" to it, and issued notices to authorities in all states and UTs to take action within two weeks.

The National Human Rights Commission (NHRC), in a statement, observed that continuation of such "illusory names may erode public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds and create confusion for public authorities" in distinguishing between a statutory body like the NHRC and NGOs.

The rights panel said it had earlier expressed concern through various platforms regarding the "misuse of its name and logo" and informed authorities concerned to take action against the people behind such "dubious organisations".

However, violations continue to come to its notice, the statement said.

The NHRC said it has been receiving complaints from individual complainants as well as non-governmental organisations (NGOs) across the country alleging violation of human rights.

"While examining these complaints, the Commission has observed that several NGOs have got themselves registered under names deceptively similar to that of the National Human Rights Commission (NHRC)," the statement said.

Recently, the Commission came across an NGO registered as 'National Human Rights Council (NHRC)', reportedly registered with the government of Delhi in 2022. Its publicity material claims, “Registered by Govt. of NITI Aayog”, “Registered by Ministry of Corporate Affairs, India”, “Registered under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India” and association with “Andhra Pradesh Human Rights Council Association”, the statement said.

Source: https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3811130-congress-leader-demands-probe-into-tribal-villagers-death?amp

Congress Leader Demands Probe into Tribal Villager's Death

Senior Congress leader Charandas Mahant has requested the National Human Rights Commission to investigate the death of a tribal villager in Chhattisgarh. The incident involved alleged administrative misconduct resulting in one death and injuries, raising concerns over human rights violations and prompting calls for justice and accountability.

Devdiscourse News Desk | Raipur | India

Updated: 19-02-2026 22:36 IST | Created: 19-02-2026 22:36 IST

Senior Congress leader Charandas Mahant has called for an independent investigation by the National Human Rights Commission (NHRC) into the death of a tribal villager in Chhattisgarh's Balrampur district.

Mahant's request follows the February 15 incident where Ram alias Ramnaresh died and two others were injured due to suspected administrative misconduct concerning illegal bauxite mining in Hanspur village. The incident has ignited distress among local communities and civil rights advocates, prompting allegations of excessive force and a severe violation of human rights.

Mahant has urged the NHRC to ascertain those responsible, ensure justice, and provide compensation and support to the victim's family while also securing medical care for the injured. Arrests have been made, including of sub-divisional magistrate Karun Dahariya.

(With inputs from agencies.)

Source: https://www.latestly.com/agency-news/india-news-karnataka-nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-mandya-chemical-plant-blast-7321249.html

India News | Karnataka: NHRC Takes Suo Motu Cognisance of Mandya Chemical Plant Blast

Get latest articles and stories on India at LatestLY. The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday took suo motu cognisance of a fatal blast at a chemical plant in the Basaralu area of Mandya district in Karnataka, which claimed two lives and left four others injured.

Agency News ANI| Feb 19, 2026 08:10 PM IST

New Delhi [India] February 19 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday took suo motu cognisance of a fatal blast at a chemical plant in the Basaralu area of Mandya district in Karnataka, which claimed two lives and left four others injured.

In an official statement, the Commission observed that the incident raises serious concerns regarding the violation of the human rights of the victims. Consequently, the NHRC has issued notices to the Karnataka Chief Secretary and the Superintendent of Police, Mandya, seeking a detailed report on the incident within two weeks. Additionally, the Commission has also sought information on the present health condition of the injured persons and details of any compensation provided to the victims or to the next of kin of the deceased.

Earlier, on February 16th, a blast occurred at a chemical plant in the Basaralu area of Mandya in Karnataka. The incident took place when a chemical storage tank was being dismantled to relocate the unit.

According to the NHRC, citing residents, the explosion was a result of negligence, as mandatory safety norms were reportedly not followed at the plant.

In a separate development, the statutory body took suo motu cognisance of a media report that 18 workers died after a blast at an illegal coal mine in the Thangskai area of East Jaintia Hills, Meghalaya, on February 5, the commission said in an official statement.

The Commission observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of the human rights of the victims. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Meghalaya, calling for a detailed report on the matter within two weeks, it added.

The report is expected to include the status of the rescue operation, compensation to the aggrieved families and police investigation, as well as steps taken/ proposed by the authorities to ensure that such incidents do not recur, the statement said. (ANI)

(The above story is verified and authored by ANI staff, ANI is South Asia's leading multimedia news agency with over 100 bureaus in India, South Asia and across the globe. ANI brings the latest news on Politics and Current Affairs in India & around the World, Sports, Health, Fitness, Entertainment, & News. The views appearing in the above post do not reflect the opinions of LatestLY)

ANI, Online News, 20/02/2026

Source: https://www.aninews.in/news/national/general-news/karnataka-nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-mandya-chemical-plant-blast20260219200123/

Karnataka: NHRC takes suo motu cognisance of Mandya chemical plant blast

ANI | February 19, 2026

New Delhi [India] February 19 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday took suo motu cognisance of a fatal blast at a chemical plant in the Basaralu area of Mandya district in Karnataka, which claimed two lives and left four others injured.

In an official statement, the Commission observed that the incident raises serious concerns regarding the violation of the human rights of the victims.

Consequently, the NHRC has issued notices to the Karnataka Chief Secretary and the Superintendent of Police, Mandya, seeking a detailed report on the incident within two weeks.

Additionally, the Commission has also sought information on the present health condition of the injured persons and details of any compensation provided to the victims or to the next of kin of the deceased.

Earlier, on February 16th, a blast occurred at a chemical plant in the Basaralu area of Mandya in Karnataka. The incident took place when a chemical storage tank was being dismantled to relocate the unit.

According to the NHRC, citing residents, the explosion was a result of negligence, as mandatory safety norms were reportedly not followed at the plant.

In a separate development, the statutory body took suo motu cognisance of a media report that 18 workers died after a blast at an illegal coal mine in the Thangskai area of East Jaintia Hills, Meghalaya, on February 5, the commission said in an official statement.

The Commission observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of the human rights of the victims. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Meghalaya, calling for a detailed report on the matter within two weeks, it added.

The report is expected to include the status of the rescue operation, compensation to the aggrieved families and police investigation, as well as steps taken/ proposed by the authorities to ensure that such incidents do not recur, the statement said. (ANI)

Source: https://www.newsonair.gov.in/nhrc-takes-suo-motu-action-against-ngos-misusing-its-name-and-logo/

NHRC takes Suo Motu action against NGOs misusing its name and logo

News On AIR | February 19, 2026 4:05 PM

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Chief Secretaries and Director Generals of Police (DGP) of all the States and Union Territories to identify NGOs misusing the name of the commission to mislead the public. Taking suo motu cognisance, the NHRC observed that some NGOs are using misleading credentials and designations of the commission. It said that continuation of such illusory names may erode public trust and lead to possible misappropriation of funds.

The Commission has asked the concerned authorities to take immediate legal action within two weeks, including cancellation of registrations obtained in violation of norms. NHRC has also directed the Chief Secretaries of Karnataka and Delhi, along with the DGP of Karnataka and the Police Commissioner of Delhi, to submit reports within two weeks regarding the action taken against the NGO.

Source: https://thenewsmill.com/2026/02/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-mandya-chemical-plant-blast-killing-two/

NHRC takes suo motu cognisance of Mandya chemical plant blast killing two

Written By: TNM (With ANI Inputs) | Published on: Feb 19, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a fatal explosion at a chemical plant in the Basaralu area of Mandya district, Karnataka, which resulted in two deaths and four injuries.

In an official statement on February 19, the Commission expressed serious concern over potential violations of the human rights of the victims. It issued notices to the Karnataka Chief Secretary and the Superintendent of Police, Mandya, requesting a detailed report on the incident within two weeks. The NHRC has also sought information on the current health condition of the injured individuals, along with details of any compensation provided to the victims or their next of kin.

The blast occurred on February 16 during the dismantling of a chemical storage tank as part of the plant's relocation. The NHRC, citing residents, indicated that the explosion appeared to result from negligence, with mandatory safety norms reportedly not being followed at the facility.

Separately, the Commission took suo motu cognisance of a media report concerning a blast at an illegal coal mine in the Thangskai area of East Jaintia Hills, Meghalaya, on February 5, which allegedly claimed 18 lives. The NHRC issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Meghalaya, requesting a detailed report within two weeks. The Commission stated that the report should cover the rescue operation status, compensation to the families affected, police investigation, and measures taken or proposed to prevent recurrence.

Source: https://www.hindustantimes.com/india-news/nhrc-flags-misuse-of-its-name-logo-by-ngos-directs-authorities-to-take-action-101771494572565-amp.html

NHRC flags misuse of its name, logo by NGOs; directs authorities to take action

Published on: Feb 19, 2026 03:19 pm IST

PTI

New Delhi, The NHRC on Thursday said it has taken cognisance of "misuse of its name and logo" by some NGOs registered under nomenclatures which are "deceptively similar" to it, and issued notices to authorities in all states and UTs to take action within two weeks.

The National Human Rights Commission , in a statement, observed that continuation of such "illusory names may erode public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds and create confusion for public authorities" in distinguishing between a statutory body like the NHRC and NGOs.

The rights panel said it had earlier expressed concern through various platforms regarding the "misuse of its name and logo" and informed authorities concerned to take action against the people behind such "dubious organisations".

However, violations continue to come to its notice, the statement said.

The NHRC said it has been receiving complaints from individual complainants as well as non-governmental organisations across the country alleging violation of human rights.

"While examining these complaints, the Commission has observed that several NGOs have got themselves registered under names deceptively similar to that of the National Human Rights Commission ," the statement said.

Recently, the Commission came across an NGO registered as 'National Human Rights Council ', reportedly registered with the government of Delhi in 2022. Its publicity material claims, "Registered by Govt. of NITI Aayog", "Registered by Ministry of Corporate Affairs, India", "Registered under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India" and association with "Andhra Pradesh Human Rights Council Association", the statement said.

A visiting card apparently related to the said organisation also bears the inscription 'Venkatesh, State Chairman, Karnataka,' it said.

Considering the gravity of the matter, it has taken suo motu cognisance of the matter.

It has observed that the name adopted and the designation 'Chairman' is "misleading and creates confusion", the statement said.

"Deceptive nomenclature misleads the public into believing that these organisations are either part of the National Human Rights Commission or recognised/authorised by it to deal with human rights issues," the NHRC flagged.

Therefore, the Commission has issued notices to the chief secretaries and director generals of police of all the states and UTs to "identify such NGOs individuals misusing the name of the NHRC or using names deceptively similar to it, and to take immediate legal action within two weeks, including cancellation of registrations obtained in violation of norms," it said.

They have also been asked to sensitise registering authorities to remain vigilant and take necessary action against defaulters.

"Additionally, in the instant matter of National Human Rights Council , the chief secretary and the director general of police, Karnataka and the chief secretary and the commissioner of police, Delhi have been further directed to

submit reports within two weeks regarding the action taken against the NGO, having its office in Karnataka and registered in Delhi," it said.

This article was generated from an automated news agency feed without modifications to text.

Source: https://orissadiary.com/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-death-of-two-persons-and-injuries-to-four-others-in-a-blast-at-a-chemical-plant-in-basaralu-area-of-mandya-district-karnataka/

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of two persons and injuries to four others in a blast at a chemical plant in Basaralu area of Mandya district, Karnataka

By: Odisha Diary Bureau
Date: February 19, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that two persons died and four others sustained grievous injuries in a blast at a chemical plant in Basaralu area of Mandya district in Karnataka on 15th February 2026. Reportedly, the local residents said that the blast was caused due to negligence as the safety norms were not being followed.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights of the victims. Therefore, it has issued notices to the state Chief Secretary and the Superintendent of Police, Mandya, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to include the status of health and compensation, if any, paid to the next of kin of the deceased and the injured persons.

According to the media report, carried on 16th February 2026, the incident happened while a chemical storage tank was being dismantled to relocate the unit.

Source: https://www.ap7am.com/en/120838/states-told-to-crack-down-on-imposters-ngos-using-names-identical-to-nhrc

States told to crack down on imposters, NGOs using names identical to NHRC

9-02-2026 Thu 15:31 | National | IANS

New Delhi, Feb 19 : The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday warned of action against imposters and NGOs that have got themselves registered under names deceptively similar to it and directed all states to crack down on them, an official said.

The NHRC sought action-taken reports from all states within two weeks, the official said in a statement.

Recently, the Commission came across an NGO registered as 'National Human Rights Council (NHRC)', reportedly registered with the Government of NCT of Delhi in 2022, said the NHRC, pointing to complaints received from individuals.

The rights panel statement said this NGO's publicity material claims, "Registered by Govt. of NITI Aayog", "Registered by Ministry of Corporate Affairs, India", "Registered under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India" and association with "Andhra Pradesh Human Rights Council Association".

A visiting card apparently related to the said organisation also bears the inscription "Venkatesh, State Chairman, Karnataka", said the NHRC statement.

Considering the gravity of the matter, it has taken suo motu cognizance of the matter. It has observed that the name adopted and the designation "Chairman" is misleading and creates confusion, it said.

Deceptive nomenclature misleads the public into believing that these organisations are either part of the National Human Rights Commission or recognised/authorised by it to deal with human rights issues, it said.

The Commission is of the view that continuation of such illusory names may erode public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds and create confusion for public authorities in distinguishing between a statutory body like the NHRC and NGOs, said the statement.

The NHRC said that it had earlier expressed concern through various platforms regarding the misuse of its name and logo and informed the authorities concerned to take action against the people behind such dubious organisations.

"However, violations continue to come to our notice," it said.

Therefore, the Commission has issued notices to the Chief Secretaries and Director Generals of Police of all the States/UTs to identify such NGOs/individuals misusing the name of the NHRC or using names deceptively similar to it and take immediate legal action within two weeks, including cancellation of registrations obtained in violation of norms, said the statement.

They have also been asked to sensitise registering authorities to remain vigilant and take necessary action against defaulters, it said.

Additionally, in the instant matter of NHRC, the Chief Secretary and the Director General of Police, Karnataka and the Chief Secretary and the Commissioner of Police, Delhi have been further directed to submit reports within two weeks regarding the action taken against the NGO, having its office in Karnataka and registered in Delhi.

Source: https://www.thehindubusinessline.com/news/nhrc-flags-misuse-of-its-name-issues-notices-to-states-for-action/article70651332.ece/amp/

NHRC flags misuse of its name, issues notices to states for action

The Commission warned that such nomenclature could erode public trust and create confusion between statutory bodies and private organisations

By PTI | Updated - February 19, 2026 at 04:34 PM. | New Delhi

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday said it has taken cognisance of "misuse of its name and logo" by some NGOs registered under nomenclatures which are "deceptively similar" to it, and issued notices to authorities in all states and UTs to take action within two weeks.

The National Human Rights Commission (NHRC), in a statement, observed that continuation of such "illusory names may erode public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds and create confusion for public authorities" in distinguishing between a statutory body like the NHRC and NGOs.

PUBLIC TRUST CONCERNS

The rights panel said it had earlier expressed concern through various platforms regarding the "misuse of its name and logo" and informed authorities concerned to take action against the people behind such "dubious organisations".

However, violations continue to come to its notice, the statement said.

VIOLATIONS CONTINUE

The NHRC said it has been receiving complaints from individual complainants as well as non-governmental organisations (NGOs) across the country alleging violation of human rights.

"While examining these complaints, the Commission has observed that several NGOs have got themselves registered under names deceptively similar to that of the National Human Rights Commission (NHRC)," the statement said.

DECEPTIVE REGISTRATIONS

Recently, the Commission came across an NGO registered as 'National Human Rights Council (NHRC)', reportedly registered with the government of Delhi in 2022. Its publicity material claims, "Registered by Govt. of NITI Aayog", "Registered by Ministry of Corporate Affairs, India", "Registered under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India" and association with "Andhra Pradesh Human Rights Council Association", the statement said.

A visiting card apparently related to the said organisation also bears the inscription 'Venkatesh, State Chairman, Karnataka,' it said.

MISLEADING DESIGNATION

Considering the gravity of the matter, it has taken suo motu cognisance of the matter.

It has observed that the name adopted and the designation 'Chairman' is "misleading and creates confusion", the statement said.

"Deceptive nomenclature misleads the public into believing that these organisations are either part of the National Human Rights Commission or recognised/authorised by it to deal with human rights issues," the NHRC flagged.

Therefore, the Commission has issued notices to the chief secretaries and director generals of police of all the states and UTs to "identify such NGOs individuals misusing the name of the NHRC or using names deceptively similar to it, and to take immediate legal action within two weeks, including cancellation of registrations obtained in violation of norms," it said.

They have also been asked to sensitise registering authorities to remain vigilant and take necessary action against defaulters.

VIGILANCE DIRECTED

“Additionally, in the instant matter of National Human Rights Council (NHRC), the chief secretary and the director general of police, Karnataka and the chief secretary and the commissioner of police, Delhi have been further directed to submit reports within two weeks regarding the action taken against the NGO, having its office in Karnataka and registered in Delhi,” it said.

Source: https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3810446-nhrc-cracks-down-on-deceptive-ngos-misusing-its-identity

NHRC Cracks Down on Deceptive NGOs Misusing its Identity

The NHRC has issued notices to all state and UT authorities to act against NGOs using deceptively similar names to the Commission. Such practices are eroding public trust and leading to potential misuse of funds. The NHRC demands immediate legal action to cancel these NGOs' registrations.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 19-02-2026 15:29 IST | Created: 19-02-2026 15:29 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has raised alarms over the misuse of its name and logo by various non-governmental organizations (NGOs) with similar-sounding titles. The commission is concerned that such nomenclatures could mislead the public and erode trust in the statutory body's mandate.

The NHRC has received multiple complaints about these organizations, some even masquerading with credentials suggesting government recognition. The matter has gained urgency with an incident involving a particular NGO named 'National Human Rights Council' registered in Delhi.

In response, the NHRC has demanded swift legal action from state and UT authorities to curb these practices. The commission has called for the cancellation of registrations obtained by misleading means to preserve the integrity of human rights advocacy in the country.

(With inputs from agencies.)

Source: https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3810451-nhrc-warns-against-ngos-misusing-its-name-orders-nationwide-crackdown?amp

NHRC Warns Against NGOs Misusing Its Name, Orders Nationwide Crackdown

In a recent case, the Commission came across an NGO registered as “National Human Rights Council (NHRC)”, reportedly registered with the Government of NCT of Delhi in 2022.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | India
Updated: 19-02-2026 16:09 IST | Created: 19-02-2026 16:09 IST

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a growing number of complaints alleging that several non-governmental organisations (NGOs) across the country are registering themselves under names deceptively similar to the statutory human rights body, misleading the public and potentially undermining trust in the Commission's mandate.

The NHRC said it has observed an alarming pattern while examining human rights complaints received from individuals and civil society groups: multiple organisations have adopted confusingly similar titles to that of the Commission, creating the false impression of official authority.

NGO Using "NHRC" Name Sparks Immediate Action

In a recent case, the Commission came across an NGO registered as "National Human Rights Council (NHRC)", reportedly registered with the Government of NCT of Delhi in 2022.

According to NHRC, the organisation's publicity material includes misleading claims such as:

"Registered by Govt. of NITI Aayog"

"Registered by Ministry of Corporate Affairs, India"

"Registered under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India"

Association with "Andhra Pradesh Human Rights Council Association"

The Commission also noted that a visiting card linked to the organisation bore the designation:

"Venkatesh, State Chairman, Karnataka."

NHRC observed that the adoption of such titles and designations is deceptive and creates public confusion.

"Misleading and Creates Confusion"

The Commission stated that the use of names resembling NHRC and titles such as "Chairman" falsely suggest that these entities are either part of the National Human Rights Commission or authorised by it.

"The name adopted and the designation 'Chairman' is misleading and creates confusion," the NHRC said.

It warned that such deceptive nomenclature may:

Erode public trust in the statutory institution

Lead to misuse of the human rights mandate

Enable misappropriation of funds

Confuse public authorities in distinguishing between NGOs and constitutional/statutory bodies

NHRC Issues Nationwide Notices to States and UTs

Given the seriousness of the matter, NHRC has issued notices to the Chief Secretaries and Directors General of Police of all States and Union Territories, directing them to:

Identify NGOs or individuals misusing the NHRC name or similar titles

Take immediate legal action within two weeks

Cancel registrations obtained in violation of norms

Sensitise registering authorities to remain vigilant against such misuse

The Commission noted that it has previously raised concerns about misuse of its name and logo, but such

violations continue.

Karnataka and Delhi Asked for Reports Within Two Weeks

In the specific case of the "National Human Rights Council (NHRC)," the Commission has issued further directions to:

Chief Secretary and Director General of Police, Karnataka

Chief Secretary and Commissioner of Police, Delhi

They have been instructed to submit detailed reports within two weeks on action taken against the NGO, which is registered in Delhi and reportedly operates an office in Karnataka.

Protecting the Integrity of Human Rights Institutions

The NHRC said the continued misuse of its name risks damaging the credibility of India's statutory human rights framework and could mislead vulnerable citizens seeking justice and protection.

The Commission's latest intervention signals a firm move to safeguard institutional integrity and prevent fraudulent organisations from exploiting the authority associated with the NHRC name.

Source: https://www.globalgovernancenews.com/nhrc-orders-nationwide-crackdown-on-fake-human-rights-bodies/

NHRC Orders Nationwide Crackdown on Fake 'Human Rights' Bodies

States told to act against NGOs misusing Commission's name and logo within two weeks
By Global Governance News On Feb 19, 2026
Suo motu action over deceptive use of NHRC identity
Notices issued to Chief Secretaries and DGPs across States/UTs
Warning on erosion of public trust and fund misuse
Separate reports sought from Delhi and Karnataka
GG News Bureau
New Delhi, 19th Feb: The National Human Rights Commission has taken suo motu cognisance of the misuse of its name and logo by certain non-governmental organisations registered under deceptively similar titles.
The Commission said it has been receiving complaints alleging human rights violations from across the country. During scrutiny, it observed that several NGOs have adopted names closely resembling that of the statutory body, potentially misleading the public.
In a recent case, an organisation registered as "National Human Rights Council (NHRC)" reportedly with the Government of NCT of Delhi in 2022 was found using publicity material claiming registration with various central agencies. A visiting card linked to the body also carried the designation "State Chairman, Karnataka", raising further concerns.
The Commission noted that such deceptive nomenclature creates confusion and may give the impression that these entities are either part of, or authorised by, the NHRC. It warned that continuation of such practices could erode public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds, and create ambiguity for authorities in distinguishing between a statutory body and private organisations.
Despite earlier alerts to concerned authorities, violations have continued, prompting the Commission to act. Notices have now been issued to Chief Secretaries and Directors General of Police of all States and Union Territories, directing them to identify such NGOs or individuals misusing the Commission's name and take legal action within two weeks, including cancellation of registrations obtained in violation of norms. Authorities have also been asked to sensitise registering agencies to remain vigilant.
Additionally, specific reports have been sought from the Chief Secretary and Director General of Police of Karnataka, as well as the Chief Secretary and Commissioner of Police of Delhi, regarding action taken against the NGO operating in Karnataka and registered in Delhi.

Source: https://vocaltv.in/national/nhrc-notice-karnataka-govtphp/cid18265998.htm

मानवाधिकार आयोग का मांड्या रासायनिक संयंत्र विस्फोट मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस

By VocalTV Desk | Feb 19, 2026, 18:49 IST

नई दिल्ली, 19 फरवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कर्नाटक के मांड्या जिले के बसरालू क्षेत्र में एक रासायनिक संयंत्र में 15 फरवरी 2026 को हुए उस विस्फोट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस मामले को लेकर आयोग ने कर्नाटक के मुख्य सचिव और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग ने 16 फरवरी को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के हवाले से बताया कि यह हादसा तब हुआ जब यूनिट को स्थानांतरित करने के लिए एक रासायनिक भंडारण टैंक को तोड़ा जा रहा था। स्थानीय लोगों का दावा है कि संयंत्र में सुरक्षा मानकों का पालन न किए जाने के कारण यह विस्फोट लापरवाही से हुआ।

आयोग ने रिपोर्ट में विशेष रूप से पीड़ितों के स्वास्थ्य उपचार और मृतकों व घायलों के परिजनों को दिए गए मुआवजे की स्थिति का विवरण भी मांगा है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी

Source: https://indiaeducationdiary.in/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-misuse-of-its-name-and-logo-by-non-governmental-organisations-ngos-registered-under-names-deceptively-similar-to-it/

NHRC, India takes suo motu cognizance of misuse of its name and logo by Non-Governmental Organisations (NGOs) registered under names deceptively similar to it

By ied news desk | February 19, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India has been receiving complaints from individual complainants as well as Non-Governmental Organisations (NGOs) across the country alleging violation of human rights. While examining these complaints, the Commission has observed that several NGOs have got themselves registered under names deceptively similar to that of the National Human Rights Commission (NHRC).

Recently, the Commission came across an NGO registered as “National Human Rights Council (NHRC)”, reportedly registered with the Government of NCT of Delhi in 2022. Its publicity material claims, “Registered by Govt. of NITI Aayog”, “Registered by Ministry of Corporate Affairs, India”, “Registered under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India” and association with “Andhra Pradesh Human Rights Council Association”. A visiting card apparently related to the said organisation also bears the inscription “Venkatesh, State Chairman, Karnataka”.

Considering the gravity of the matter, it has taken suo motu cognizance of the matter. It has observed that the name adopted and the designation “Chairman” is misleading and creates confusion. Deceptive nomenclature misleads the public into believing that these organisations are either part of the National Human Rights Commission or recognised/ authorised by it to deal with human rights issues.

The Commission is of the view that continuation of such illusory names may erode public trust, lead to misuse of mandate, possible misappropriation of funds and create confusion for public authorities in distinguishing between a statutory body like NHRC and NGOs.

The Commission had earlier expressed concern through various platforms regarding the misuse of its name and logo and informed the authorities concerned to take action against the people behind such dubious organisations. However, violations continue to come to its notice.

Therefore, the Commission has issued notices to the Chief Secretaries and Director Generals of Police of all the States/ UTs to identify such NGOs/ individuals misusing the name of the National Human Rights Commission or using names deceptively similar to it and take immediate legal action within two weeks, including cancellation of registrations obtained in violation of norms. They have also been asked to sensitise registering authorities to remain vigilant and take necessary action against defaulters.

Additionally, in the instant matter of National Human Rights Council (NHRC), the Chief Secretary and the Director General of Police, Karnataka and the Chief Secretary and the Commissioner of Police, Delhi have been further directed to submit reports within two weeks regarding the action taken against the NGO, having its office in Karnataka and registered in Delhi.

Source: https://newsable.asianetnews.com/india/karnataka-chemical-plant-blast-nhrc-issues-notice-seeks-report-articleshow-blbubsa

Karnataka chemical plant blast: NHRC issues notice, seeks report

2 Min read
Author : Asianet News Central | ANI
Published : Feb 19 2026, 08:31 PM IST

The NHRC has taken suo motu cognisance of a fatal chemical plant blast in Mandya, Karnataka, and an illegal coal mine blast in Meghalaya. It has issued notices to both state governments seeking detailed reports on the incidents within two weeks.

Karnataka Chemical Plant Blast

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday took suo motu cognisance of a fatal blast at a chemical plant in the Basaralu area of Mandya district in Karnataka, which claimed two lives and left four others injured. In an official statement, the Commission observed that the incident raises serious concerns regarding the violation of the human rights of the victims.

Consequently, the NHRC has issued notices to the Karnataka Chief Secretary and the Superintendent of Police, Mandya, seeking a detailed report on the incident within two weeks. Additionally, the Commission has also sought information on the present health condition of the injured persons and details of any compensation provided to the victims or to the next of kin of the deceased.

Earlier, on February 16th, a blast occurred at a chemical plant in the Basaralu area of Mandya in Karnataka. The incident took place when a chemical storage tank was being dismantled to relocate the unit. According to the NHRC, citing residents, the explosion was a result of negligence, as mandatory safety norms were reportedly not followed at the plant.

Meghalaya Mine Blast

In a separate development, the statutory body took suo motu cognisance of a media report that 18 workers died after a blast at an illegal coal mine in the Thangskai area of East Jaintia Hills, Meghalaya, on February 5, the commission said in an official statement. The Commission observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of the human rights of the victims. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Meghalaya, calling for a detailed report on the matter within two weeks, it added. The report is expected to include the status of the rescue operation, compensation to the aggrieved families and police investigation, as well as steps taken/ proposed by the authorities to ensure that such incidents do not recur, the statement said. (ANI)

(Except for the headline, this story has not been edited by Asianet Newsable English staff and is published from a syndicated feed.)

Source: https://www.tribuneindia.com/news/delhi/hc-seeks-answers-from-cops-centre-state-rights-panel/amp

HC seeks answers from cops, Centre, state, rights panel

807 missing in 15 days

Shekhar Singh | Tribune News Service | New Delhi, Updated At : 09:15 AM Feb 19, 2026 IST

Unlock Exclusive Insights with The Tribune Premium
Thought-provoking Opinions, Expert Analysis, In-depth Insights and other Member Only Benefits

The Delhi High Court (HC) on Wednesday sought responses from the Delhi Police, the Union Government, the Delhi Government and the National Human Rights Commission (NHRC) on a plea seeking action over the reported disappearance of more than 800 individuals from the national capital within the first 15 days of 2026.

A Division Bench comprising Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tejas Karia issued notice and granted four weeks' time to the respondent authorities to place their stand on record. The HC has allowed two weeks thereafter for the petitioner to file a rejoinder.

The order followed the hearing of a public interest litigation (PIL) filed by Jayeeta Deb Sarkar. The plea drew attention to a recent news report stating that between January 1 and January 15, as many as 807 persons were reported missing across the Capital. The report triggered public concern over the scale and timing of the disappearances.

Source: https://organizeindia.in/leaderofopposition-writes-nhrc/

बलरामपुर में आदिवासी ग्रामीण की मौत का मामला, नेता प्रतिपक्ष ने NHRC और जनजाति आयोग को लिखा पत्र

4 hours ago admin

छत्तीसगढ़ की सियासत में बलरामपुर के हंसपुर गांव की घटना को लेकर हलचल तेज हो गई है. छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एक आदिवासी ग्रामीण की कथित प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान हुई मौत को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया है. उन्होंने इस मसले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा है.

डॉ. चरणदास महंत ने अपने बयान में कहा कि हंसपुर गांव में घटी घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक निर्दोष आदिवासी ग्रामीण की जान चली गई. उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की घटना स्वीकार्य नहीं हो सकती.

नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में उल्लेख किया कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा कथित रूप से आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया. इस घटना के बाद स्थानीय समुदायों में गहरा आक्रोश और भय का वातावरण है. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक जवाबदेही, कानून के शासन और मूलभूत मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं. नेता प्रतिपक्ष ने यह भी मांग की है कि मृतक के परिवार को तत्काल आर्थिक मुआवजा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए. साथ ही घटना में प्रभावित एवं घायल ग्रामीणों के समुचित इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

हंसपुर की घटना ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष इसे आदिवासी अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बता रहा है, वहीं अब सबकी नजर आयोग की आगामी कार्रवाई पर टिकी है. आने वाले दिनों में यह मुद्दा विधानसभा और राजनीतिक मंचों पर और अधिक गरमा सकता है.

Source: https://thepatriot.in/crime/delhi-missing-persons-surge-draws-scrutiny-as-rights-panel-intervenes-81983

Delhi: Missing persons surge draws scrutiny as rights panel intervenes

Cover Story - February 19, 2026 | By : Kushan Niyogi

NHRC takes suo motu cognisance amid court notices, trafficking concerns and emerging crime patterns in the national capital

While Delhi Police has increasingly doubled down on recent reports of a rise in the total number of missing people, the National Human Rights Commission's (NHRC) decision to take suo motu cognisance has added a fresh layer of scrutiny to the situation.

On February 11, the Delhi High Court sent notices to the Commissioner of Police and the Chief Secretary of the Delhi Government, seeking a detailed response to claims raised in a Public Interest Litigation (PIL) filed the same day. While labelling the PIL as frivolous, the court listed the matter for further hearing on February 18.

Rising numbers and police response

According to ZIPNET data, from November 1, 2025, to February 12, 2026, a total of 7,318 missing persons were recorded in the national capital. During the same period in the previous winter season, around 5,000 remained untraced since 2024, while 2,563 people were marked as traced.

Police officials have attributed the figures to several factors, including increased vigilance, enhanced tracking systems, and improved collaboration with non-governmental organisations. A senior police officer said comprehensive efforts have been launched to tackle human trafficking, highlighting that dedicated teams, better surveillance, and the strategic use of CCTV cameras have improved the ability to trace missing persons and prevent trafficking.

"However, some of them run off by their own accord. It is difficult to track them, or if the person is an adult," he said.

Even in 2024, the number of untraced missing persons dropped to 22,040 cases compared to 24,356 in 2023, reflecting a 9.5 % decline. However, the ratio remains stark, as for every individual located, two others remain untraced.

From January 1, 2024, to January 1, 2025, Delhi Police recovered 9,377 missing individuals, down from 10,566 in the previous comparable period. While these figures reflect progress, they also expose persistent gaps in the system.

District-wise trends

The figures show that the North East district recorded the highest number of unresolved cases, with 734 individuals still missing, followed by the Outer North district with 731 and the Outer district with 682.

Significant numbers were also reported in South West (635), South East (589), South (565), and Dwarka (529) districts. In contrast, more central or specialised zones showed relatively lower figures, with the North district at 286, Rohini at 435, and the East district at 438.

The districts of West (385), Shahdara (297), Central (296), and North West (288) remain areas of concern, while the Railway zone (60) and the New Delhi district (41) reported the fewest instances of untraced individuals.

Anti-trafficking operations

One of the key contributors to the reduction in trafficking cases has been the Anti-Human Trafficking Units (AHTUs) under Delhi Police. Launched as part of a 2010 Ministry of Home Affairs scheme, these units were created to address human trafficking through a coordinated, systemic approach.

The scheme mandated specialised units in every district, focusing on prevention, rescue, rehabilitation, and

prosecution. These units conduct raids and rescue operations while offering survivors counselling and vocational training. Each AHTU comprises trained inspectors, sub-inspectors, and constables who work in close coordination with social welfare departments and other stakeholders. This integrated model has enabled police to dismantle complex trafficking networks with greater accuracy.

AHTUs also spearhead Operation Muskaan, a flagship initiative aimed at rescuing trafficked children. As of October 30, 2024, 989 children were rescued in 97 cases, compared to 1,257 children in 126 cases in 2023.

Many rescued children were subjected to exploitative labour, working long hours in hazardous conditions for meagre wages. While the dip in numbers may suggest success, the persistence of child labour remains a major concern as traffickers evolve their methods. A senior police officer said increased surveillance and strategically placed units have enabled authorities to crack down on these networks tirelessly.

Placement agencies and forced labour

A new and more insidious challenge has emerged involving placement agencies exploiting legal loopholes to employ minors. These agencies often place children as domestic workers in households or businesses where they are paid paltry sums and subjected to exploitative conditions.

According to Delhi Police, while intra-city child trafficking is relatively uncommon, Delhi's geographical position near Gurugram and Noida has turned it into a hub for trafficking. Many children are brought into the city and pushed into forced labour, with placement agencies playing a pivotal role.

Although the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, prohibits the employment of children under 14 and restricts hazardous work for those aged between 14 and 18, violations continue with alarming regularity.

Organ trafficking networks exposed

Another persistent factor is organ harvesting in the national capital. In recent months, the city has been shaken by the exposure of a sophisticated international organ trafficking network, highlighting the grim reality of the "red market" operating within the city's shadows.

According to recent reports from Delhi Police and central agencies, a major organ harvesting racket was dismantled following investigations into several private hospitals and suspicious medical tourism activities. The syndicate primarily targeted vulnerable individuals from neighbouring countries, particularly Bangladesh, luring them with the promise of high-paying jobs or financial relief from debts, only to coerce them into "donating" their kidneys for a fraction of the promised sum.

Investigations revealed traffickers manipulated legal loopholes and forged documentation to bypass the strict requirements of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act. In July 2024, Delhi Police arrested a high-profile transplant surgeon allegedly linked to numerous illegal surgeries.

It is reported that the syndicate charged wealthy recipients—many of whom travelled to Delhi specifically for these procedures—upwards of Rs 49,33,488 and Rs 61,66,860 per transplant. Meanwhile, donors, often impoverished labourers, were frequently left with significant medical complications and paid as little as Rs 2.4 lakh, if they were paid at all.

The scale of the operation prompted a wider crackdown by the National Investigation Agency (NIA), which recently apprehended key figures in an Iran-linked organ trade ring that used Delhi as a transit and recruitment hub. These networks allegedly operated under the guise of legitimate medical tourism, using social media to connect with prospective donors and recipients.

To maintain a veneer of legality, the criminals fabricated "No Objection Certificates" and created fake family trees to present donors as close relatives of patients, exposing lapses in hospital authorisation committees' vetting processes.

Rights panel intervention

In response to these developments, the NHRC has issued notices to the Delhi Government and Delhi Police, demanding more stringent monitoring of transplant centres.

Public health experts note that while India has reached record numbers of legal transplants in 2024 and 2025, the massive gap between organ demand and supply from deceased donors continues to fuel the black market.

Authorities are now pushing for the establishment of a dedicated State Organ and Tissue Transplant Organisation (SOTTO) in Delhi to improve transparency and ensure that every transplant is conducted ethically and within the bounds of the law.

Changing nature of trafficking

The nature of these crimes is also shifting, with many trafficking cases now being reclassified as kidnappings, which may contribute to lower reported figures.

Experts say the situation is no longer as straightforward as it once was. Some workers in brothels, for instance, are now sent by their families or arrive voluntarily rather than being abducted.

Source: https://www.indiatoday.in/india/story/harbinder-sandhu-tarn-taran-sarpanch-murder-majha-gangs-rivalries-killings-police-aap-government-2871006-2026-02-19

How Punjab Sarpanch murder exposes Majha gangs, killings, police in deadly loop

With Harbinder Sandhu's murder being the third killing of a local leader in recent months, opposition parties have questioned the Aam Aadmi Party government's ability to control gang violence ahead of the upcoming state elections.

Aman Kumar Bhardwaj | Chandigarh, UPDATED: Feb 19, 2026 16:42 IST

Edited By: Vivek Kumar

The killing of Sarpanch Harbinder Sandhu in Punjab's Tarn Taran has once again pushed the state's worsening gang rivalry into sharp focus, raising serious concerns over law and order ahead of the upcoming Assembly elections. Shot dead during a wedding function, Sandhu's murder marks the third killing of a local leader in recent months, intensifying political criticism of the ruling Aam Aadmi Party (AAP) government and reviving questions about the state's ability to curb organised crime.

THE KILLING THAT RANG THE BELLS

Police sources told India Today, two unidentified assailants opened fire at Sidhu Farm, where Sandhu had gone to attend a wedding.

Investigators suspect the attackers used high-powered weapons, including an AK-series assault rifle and a 9mm pistol — a chilling reminder of the 2022 assassination of Punjabi singer Sidhu Moosewala, in which similar firearms were used.

Sandhu succumbed to her injuries on the way to the hospital, while another man, Garman Singh, sustained a leg injury while attempting to chase the attackers.

GANG RIVALRIES IN MAJHA

The murder is being viewed against the backdrop of escalating gang rivalries in Punjab's Majha belt.

In January, the Sarpanch of Valtoha in Tarn Taran was killed, followed by the murder of local leader Lucky Oberoi. Sandhu, the Sarpanch of Thathian Mahanta, becomes the third political functionary to be gunned down, triggering sharp reactions from opposition leaders who have questioned the security of AAP's own representatives.

If elected leaders are unsafe, critics argue, what assurance can ordinary citizens expect?

In a provocative development, the Landa Harike gang claimed responsibility for the killing through a viral social media post.

The gang alleged that Sandhu had testified in an extortion case against Sukhwinder Singh alias "Noni," an associate, and suggested that her role as a witness led to the attack.

The post also carried open threats directed at law enforcement, reflecting the brazenness with which gangs are using social media to spread fear and assert dominance.

The roots of the conflict trace back to a 2024 extortion complaint filed by a businessman against Noni, in which Sandhu was listed as a co-complainant.

Noni was later killed, followed by the murder of another figure, Happy Chaudhary, further deepening tensions between rival groups such as the Satta Naushera, Landa Harike and Gurdev Gehshal gangs.

THE EMERGENCE OF DOLLY BAL GANG

Police sources said the emergence of the Dolly Bal gang has added another volatile layer to the region's already fragile security landscape.

While initial investigations suggest a possible personal enmity angle, multiple police teams are examining CCTV footage and forensic evidence.

In a significant administrative move, DSP Patti Jagbir Singh and SHO Sarhali Gurvinder Singh have been suspended for alleged lapses in preventive policing.

POLICE CRACKDOWN ON GANGS

Punjab's Director General of Police, Gaurav Yadav, had earlier stated that since April 2022, the police have conducted 324 encounters with alleged gangsters, resulting in 24 deaths and over 500 arrests.

However, these operations have also drawn scrutiny. The National Human Rights Commission has sought a report over allegations of extra-judicial killings, even as encounter cases continue to rise.

Between November 2025 and January 2026 alone, 34 encounters were recorded, with five deaths and several injuries.

Police maintain that most incidents involved retaliatory firing in self-defence.

CRACKDOWN INVITES JUDICIAL CRITICISM

Judicial criticism has added to the pressure. The Punjab and Haryana High Court recently observed that the state's anti-gang campaign, "Operation Prahar," appeared more like publicity than effective enforcement.

The court questioned the intelligence network's efficiency and stressed accountability over optics.

With Punjab heading to the polls in ten months, the growing cycle of gang violence, retaliatory killings and police encounters has become a defining political issue.

Source: https://www.ucanews.com/amp/an-alibi-for-a-triple-murder-in-indias-odisha-state/111932

An alibi for a triple murder in India's Odisha state

The Soren family murders fit a disturbing pattern of violence against Christians in the eastern state's tribal areas
John Dayal | Updated: February 19, 2026 03:58 AM GMT
Twenty-seven years after Graham Staines and his two sons were burned alive in their station wagon in Odisha's Keonjhar district on Jan. 22, 1999, police have recorded another brutal crime in the same district.
On the night of Jan. 25 this year, Jitendra Soren, his wife Malati, and their 15-year-old daughter Mami were hacked to death inside their home in Nialijharan village. The official narrative by the state police and media attributes the killings to a long-standing land dispute with relatives.
However, the surviving son's testimony reveals a darker truth. The Soren family had recently converted to Christianity and attended worship services just a week before their deaths.
In a village with very few Christians, their conversion was seen as intolerable, the son said.
The accused did not merely want the family's land — they wanted to punish them for their religious choice.
The use of witchcraft accusations — an entrenched method of vilifying tribal Christians in Odisha — served as a pretext to justify the killings. This pattern of using superstitions to target religious minorities has a long history in the region.
The First Information Report (FIR) fails to mention religious enmity, and this absence is telling. The official narrative downplays the religious motives of the crime, framing it instead as an ordinary family dispute.
The Soren family murders fit a disturbing pattern of violence against Christians in Odisha and across India, especially in tribal regions.
The media in the state has made common cause with the police and politicians in sanitizing or erasing the religious motives behind such crimes.
The political climate in Odisha, alongside rising anti-Christian violence in BJP-ruled states, complicates understanding this tragedy. The attackers sought not only the family's land but also to punish them for their faith.
The Soren children are caught in a painful bind. The elder married daughter who filed the complaint is not Christian; the younger daughter who escaped is. The son, studying at college, is Christian.
The surviving children are now refugees in their own district. The younger daughter cannot return home, and the son cannot mourn his parents without fear. They are powerless to correct the narrative. In this silence, the police narrative became accepted truth.
The accused could not have crafted a more effective justification.
Witchcraft allegations against tribal Christians follow a grim, recurring pattern. In June 2020, fifteen-year-old Samaru Madkami of Malkangiri district was dragged from his home and beaten to death after villagers accused him of witchcraft.
He was one of only three Christian families in his Koya tribal village. Six people were arrested; the accused confessed. Archbishop John Barwa condemned the charges as false and baseless, weaponized against converts.
The Soren case echoes this script, replayed six years later in another district.
Tribal areas in Odisha face genuine land alienation. The Orissa High Court recently nullified fraudulent sales of Scheduled Caste ancestral land in Keonjhar, noting that illiterate sellers were unaware of the implications of their thumbprints.
The National Human Rights Commission has highlighted that superstition in Keonjhar causes dozens of murders every year, worsened by denial of basic amenities.

Yet economic conflict differs from communal persecution. The Sorens owned land. They were not impoverished litigants. Their conversion did not create the land dispute; it made them vulnerable to one being fabricated.

The 1967 Orissa Freedom of Religion Act, among the first of now 12 such laws in states, prohibits conversion by force, inducement, or fraudulent means, defining inducement broadly.

Missionaries provide education and healthcare, and the law increasingly seems to justify these as also coming under the definition of allurement.

This murder's geography and politics make it especially chilling. Keonjhar is not neutral ground in anti-Christian violence; it is ground zero.

Dara Singh, convicted of burning Graham Staines and his sons alive, remains imprisoned — but barely. In April 2025, co-convict Mahendra Hembram was released from Keonjhar jail for good behaviour and garlanded by supporters.

Odisha's Chief Minister, Mohan Majhi, who was the local MLA at the time, publicly campaigned for Dara Singh's release, even staging a hunger strike. He is a resident of the district where the recent murders were committed.

Since the BJP took office in May 2024, communal incidents in Odisha have risen sharply. In December 2024, two women in Balasore were tied to trees and beaten on suspicion of forced conversion — accusations never proven.

In August 2025, Catholic clergy vehicles in Jaleswar were stopped by groups alleging conversion efforts. In distant Kerala, the Marxist chief minister condemned the incident as Hindutva vigilantism and a communal witch-hunt.

In December 2025, vendors selling Christmas items in Puri were heckled by right-wing groups insisting the temple town belonged solely to Hindus. None of these incidents drew official condemnation from the chief minister.

The Centre for the Study of Organized Hate noted a 41% increase in anti-Christian hate speech incidents in 2025, with many occurring in BJP-ruled states.

This climate of impunity has dire consequences. In Chhattisgarh, Pastor Samuel Masih was assaulted, and Dalit Christian families face eviction and discrimination. Across India, congregations meet in secret, fearful of misinterpretation.

Only three families in the village converted to Christianity in the past year. This is not a demographic wave; it is a quest for faith in a country that guarantees this right. If three families converting can provoke such violence, the issue lies not with the conversion but with the brutality that follows.

The murders of Jitendra, Malati, and Mami Soren cannot be reduced to a simple land dispute. They were murdered because of their faith in a community that had already decided which gods were acceptable.

President Droupadi Murmu and former Comptroller and Auditor General G.C. Murmu, both from neighboring Mayurbhanj, remain silent. The USCIRF continues to designate India a Country of Particular Concern, a designation the government rejects.

*The views expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official editorial position of UCA News.

Source: https://mradubhashi.com/news.php?id=charandas-mahant-wrote-to-the-national-human-rights-commission-regarding-the-death-of-an-elderly-man-in-balrampur-accusing-the-sdm-of-murder-605162

बलरामपुर में बुजुर्ग की मौत को लेकर चरणदास महंत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र, SDM पर हत्या का आरोप

Updated on 19 Feb, 2026 04:28 PM IST BY MRADUBHASHI.COM

CG News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 16 फरवरी को कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई थी. इस मारपीट के कारण एक बुजुर्ग की मौत हो गई. आरोप है कि SDM द्वारा ग्रामीणों से मारपीट की गई थी. अब इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए उन्होंने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

जांच के लिए चरणदास महंत ने लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में एक बुजुर्ग आदिवासी की मृत्यु के मामले में हस्तक्षेप किया है. उन्होंने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र लिखा है. उन्होंने इस घटना को मानवता पर कलंक बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

डॉ. चरणदास महंत ने अपने पत्र में लिखा है कि हंसपुर गांव में SDM स्तर के अधिकारी द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक निर्दोष बुजुर्ग आदिवासी की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर हुई इस घटना ने प्रशासनिक जवाबदेही और आदिवासी समुदाय के मौलिक अधिकारों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला 16 फरवरी 2026 का है. बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में SDM करुण कुमार डहरिया और उनकी टीम अवैध उत्खनन रोकने के लिए पहुंची थे. आरोप है कि इस दौरान SDM करुण और उनकी टीम ने बिना कोई पूछताछ किए सीधे ग्रामीणों मारपीट शुरू कर दी. SDM करुण डहरिया पर 3 ग्रामीणों के साथ मारपीट के आरोप हैं. इनमें से एक ग्रामीण की मौत हो गई. इस पूरे मामले में SDM करुण डहरिया को निलंबित भी कर दिया गया है.

Source: https://www.hindi.awazthevoice.in/india-news/karnataka-nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-mandya-chemical-plant-blast-83268.html

कर्नाटक: NHRC ने मांड्या केमिकल प्लांट ब्लास्ट का स्वतः संज्ञान लिया

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by onikamaheshwari | Date 19-02-2026

नई दिल्ली

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने गुरुवार को कर्नाटक के मांड्या जिले के बसरालू इलाके में एक केमिकल प्लांट में हुए जानलेवा ब्लास्ट का खुद से संज्ञान लिया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। एक ऑफिशियल बयान में, कमीशन ने कहा कि यह घटना पीड़ितों के ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। इसलिए, NHRC ने कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी और मांड्या के पुलिस सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी करके दो हफ़्ते के अंदर घटना पर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है।

इसके अलावा, कमीशन ने घायल लोगों की अभी की हेल्थ कंडीशन और पीड़ितों या मरने वालों के परिवार वालों को दिए गए किसी भी मुआवज़े की डिटेल्स भी मांगी हैं।

इससे पहले, 16 फरवरी को, कर्नाटक के मांड्या के बसरालु इलाके में एक केमिकल प्लांट में ब्लास्ट हुआ था। यह घटना तब हुई जब यूनिट को दूसरी जगह ले जाने के लिए एक केमिकल स्टोरेज टैंक को तोड़ा जा रहा था।

NHRC के अनुसार, लोगों के हवाले से, यह धमाका लापरवाही का नतीजा था, क्योंकि प्लांट में ज़रूरी सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया था। एक अलग डेवलपमेंट में, कानूनी संस्था ने एक मीडिया रिपोर्ट पर खुद से संज्ञान लिया कि 5 फरवरी को मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स के थांगस्काई इलाके में एक गैर-कानूनी कोयला खदान में ब्लास्ट के बाद 18 मज़दूरों की मौत हो गई, कमीशन ने एक ऑफिशियल बयान में कहा।

कमीशन ने देखा कि अगर न्यूज़ रिपोर्ट की बातें सच हैं, तो यह पीड़ितों के ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती हैं। इसलिए, उसने मेघालय के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी करके दो हफ़्ते के अंदर मामले पर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है।

बयान में कहा गया है कि रिपोर्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन का स्टेटस, पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा और पुलिस जांच, साथ ही अधिकारियों द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम शामिल होने की उम्मीद है ताकि यह पक्का हो सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

Source: https://hindi.theprint.in/india/chhattisgarh-mahant-writes-to-human-rights-commission-to-investigate-tribal-mans-death-case/935904/

छत्तीसगढ़: आदिवासी की मौत के मामले की जांच के लिए महंत ने मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र

भाषा | 19 February, 2026

रायपुर, 19 फरवरी (भाषा) छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पत्र लिखकर बलरामपुर जिले में एक आदिवासी ग्रामीण की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी रामासुब्रमण्यन को 18 फरवरी को लिखे पत्र में महंत ने हंसपुर गांव में हुई घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि इस कार्रवाई में नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने बहुत ज्यादा बल का इस्तेमाल किया, और नतीजतन एक बेगुनाह आदिवासी की मौत हो गई।

महंत ने पत्र में कहा है कि इस घटना ने स्थानीय समुदायों और सिविल सोसाइटी में दुख और परेशानी पैदा की है, जिससे प्रशासन का व्यवहार, जवाबदेही और बुनियादी मानवाधिकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

उन्होंने लिखा, "मेरा मानना है कि न केवल तथ्यों को स्थापित करने के लिए, बल्कि न्याय और कानून के शासन में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए भी एक पूरी, निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच जरूरी है।"

नेता प्रतिपक्ष ने घटना में घायल ग्रामीणों का बेहतर इलाज का भी अनुरोध किया है।

बलरामपुर जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र के हंसपुर गांव में 15 फरवरी को गैर-कानूनी बॉक्साइट खनन के शक में कथित तौर पर कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। इस घटना में राम उर्फ रामनरेश की मृत्यु हो गई तथा अजीत राम (60) और आकाश अगरिया (20) घायल हो गए।

इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं कुसमी क्षेत्र के एसडीएम करुण डहरिया तथा तीन अन्य विक्की सिंह उर्फ अजय प्रताप सिंह, मंजीत कुमार यादव और सुदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना के बाद एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है।

भाषा संजीव खारी

खारी

यह खबर 'भाषा' न्यूज़ एजेंसी से 'ऑटो-फीड' द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

Source: https://www.etvbharat.com/hi/state/cg-lop-charandas-mahant-demands-nhrc-probe-in-balrampur-tribal-villager-death-chhattisgarh-news-cts26021904337

बलरामपुर में आदिवासी ग्रामीण की मौत का मामला, नेता प्रतिपक्ष ने NHRC और जनजाति आयोग को लिखा पत्र

हंसपुर आदिवासी मौत मामला, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष महंत ने NHRC और जनजाति आयोग को लिखा पत्र, मुआवजा देने और उच्चस्तरीय जांच की मांग

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 19, 2026 at 4:31 PM IST

3 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ की सियासत में बलरामपुर के हंसपुर गांव की घटना को लेकर हलचल तेज हो गई है. छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एक आदिवासी ग्रामीण की कथित प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान हुई मौत को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया है. उन्होंने इस मसले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा है.

लोकतंत्र में इस तरह की घटना अस्वीकार्य- महंत

डॉ. चरणदास महंत ने अपने बयान में कहा कि हंसपुर गांव में घटी घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक निर्दोष आदिवासी ग्रामीण की जान चली गई. उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की घटना स्वीकार्य नहीं हो सकती.

प्रशासनिक आचरण पर उठे सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में उल्लेख किया कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा कथित रूप से आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया. इस घटना के बाद स्थानीय समुदायों में गहरा आक्रोश और भय का वातावरण है. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक जवाबदेही, कानून के शासन और मूलभूत मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं.

इस केस में निष्पक्ष जांच की जरूरत है. तथ्यों की जांच और दोषियों की जवाबदेही तय करने के लिए व्यापक और निष्पक्ष जांच आवश्यक है. मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से स्वतंत्र रूप से पूरे मामले की जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग करता हूं, ताकि जनता का कानून व्यवस्था पर विश्वास कायम रह सके- डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़

पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा और पुनर्वास की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी मांग की है कि मृतक के परिवार को तत्काल आर्थिक मुआवजा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए. साथ ही घटना में प्रभावित एवं घायल ग्रामीणों के समुचित इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

हंसपुर की घटना ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष इसे आदिवासी अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बता रहा है, वहीं अब सबकी नजर आयोग की आगामी कार्रवाई पर टिकी है. आने वाले दिनों में यह मुद्दा विधानसभा और राजनीतिक मंचों पर और अधिक गरमा सकता है.

Source: https://panchjanya.com/2026/02/19/458957/bharat/karnataka-mandya-chemical-plant-blast-nhrc-notice/

कर्नाटक केमिकल प्लांट ब्लास्ट पर NHRC सख्त! सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जबाव

Written by एजेंसी — edited by Shivam Dixit Feb 19, 2026, 08:22 pm IST in भारत, कर्नाटक

नई दिल्ली (हि.स.) । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कर्नाटक के मांड्या जिले के बसरालू क्षेत्र में एक रासायनिक संयंत्र में 15 फरवरी 2026 को हुए उस विस्फोट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

मुख्य सचिव और एसपी को नोटिस जारी

इस मामले को लेकर आयोग ने कर्नाटक के मुख्य सचिव और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई

आयोग ने 16 फरवरी को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के हवाले से बताया कि यह हादसा तब हुआ जब यूनिट को स्थानांतरित करने के लिए एक रासायनिक भंडारण टैंक को तोड़ा जा रहा था। स्थानीय लोगों का दावा है कि संयंत्र में सुरक्षा मानकों का पालन न किए जाने के कारण यह विस्फोट लापरवाही से हुआ।

मुआवजे और उपचार की जानकारी मांगी

आयोग ने रिपोर्ट में विशेष रूप से पीड़ितों के स्वास्थ्य उपचार और मृतकों व घायलों के परिजनों को दिए गए मुआवजे की स्थिति का विवरण भी मांगा है।

Source: https://www.livehindustan.com/ncr/new-delhi/story-nhrc-takes-action-against-ngos-misusing-its-name-and-logo-201771499063916.html

एनएचआरसी ने अपने नाम, लोगो के दुरुपयोग पर स्वतः संज्ञान लिया

Feb 19, 2026 04:34 pm IST Newswrap हिन्दुस्तान , नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने नाम और लोगो के दुरुपयोग का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पाया कि कई एनजीओ भ्रामक नामों से पंजीकृत हैं, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें कर रहे हैं। आयोग ने ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने नाम और लोगो के एनजीओ द्वारा दुरुपयोग का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को बताया कि आयोग को देशभर के व्यक्तियों और एनजीओ से मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों की जांच करते हुए आयोग ने पाया है कि कई गैर-सरकारी संगठनों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से मिलते-जुलते भ्रामक नामों से अपना पंजीकरण करा लिया है। उन्होंने कहा कि आयोग को राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद (एनएचआरसी) के रूप में पंजीकृत एक गैर-सरकारी संगठन के बारे में पता चला, जो कथित तौर पर 2022 में दिल्ली सरकार से पंजीकृत है। इसके प्रचार सामग्री में यह दावा किया गया है कि संगठन नीति आयोग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत पंजीकृत और आंध्र प्रदेश मानवाधिकार परिषद संघ से संबद्ध है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पाया है कि अपनाया गया नाम और अध्यक्ष पदनाम भ्रामक है और भ्रम पैदा करता है। भ्रामक नामकरण से जनता को यह विश्वास होने लगता है कि ये संगठन या तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हिस्सा हैं या फिर मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर काम करने के लिए आयोग द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश आयोग ने इससे पहले विभिन्न मंचों के माध्यम से अपने नाम और लोगो के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की थी और संबंधित अधिकारियों को ऐसे संदिग्ध संगठनों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम का दुरुपयोग करने वाले या इससे मिलते-जुलते भ्रामक नामों का उपयोग करने वाले गैर-सरकारी संगठनों या व्यक्तियों की पहचान करें। इसके साथ ही ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है।

Source: https://www.jagran.com/punjab/amritsar-encounters-in-last-months-punjab-police-custody-nhrc-notice-40147564.html

324 मुठभेड़ों का आंकड़ा और 24 मौतें, पंजाब पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल; एनएचआरसी नोटिस के बाद भी जवाब लंबित

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Thu, 19 Feb 2026 05:37 PM (IST)

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की तरफ से दिए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2022 से 324 मुठभेड़ों में 24 मौतें हुईं और 515 गिरफ्तार हुए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने "राज्य प्रायोजित फर्जी मुठभेड़ों" के आरोपों पर नोटिस जारी किया है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है।

HighLights

अप्रैल 2022 से 324 मुठभेड़ों में 24 मौतें हुईं।
NHRC ने फर्जी मुठभेड़ों पर नोटिस दिया, जवाब लंबित।
कई मुठभेड़ें हिरासत में लिए गए आरोपियों के साथ हुईं।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में पुलिस मुठभेड़ों को लेकर बहस तेज हो गई है। राज्य में पुलिस कार्रवाई पर पहली बार आधिकारिक बयान देते हुए पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि अप्रैल 2022 से, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब से अब तक राज्य पुलिस ने “गैंगस्टरों के साथ 324 मुठभेड़ें” दर्ज की हैं।

इन मुठभेड़ों में 24 की मौत हुई और 515 गिरफ्तार किए गए। डीजीपी ने बताया था कि गिरफ्तार किए गए 515 गैंगस्टरों में से 319 को गोली लगी। यह बयान उस समय आया जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पंजाब के गृह सचिव को “राज्य प्रायोजित फर्जी मुठभेड़ों” के आरोपों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) दाखिल करने का नोटिस जारी किया था।

दो महीने बीतने के बाद भी राज्य सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है।

तीन महीनों में 34 और मुठभेड़ें

डीजीपी के बयान के बाद भी मुठभेड़ों का सिलसिला जारी रहा। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच तीन महीनों में पंजाब पुलिस ने 34 मुठभेड़ों की रिपोर्ट दी — यानी औसतन हर तीन दिन में एक। इनमें पांच की मौत हुई और 45 घायल हुए। इनमें से 15 मुठभेड़ें केवल जनवरी महीने में हुईं।

इन मुठभेड़ों में कई समानताएं सामने आईं। पुलिस का सबसे सामान्य तर्क “आत्मरक्षा” (सेल्फ-डिफेंस) रहा। एक-तिहाई से अधिक मुठभेड़ें तब हुईं जब आरोपी पहले से पुलिस हिरासत में थे और उन्हें हथियार बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। कई मामलों में पुलिस ने कहा कि “हथकड़ी लगे” आरोपियों ने छिपाया हुआ हथियार निकालकर फायरिंग कर दी।

कई मामलों में पुलिसकर्मी भी घायल हुए

कम से कम आठ मामलों में पुलिस ने दावा किया कि उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, लेकिन पुलिसकर्मी बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से बच गए। कई बार गोलियां पुलिस वाहनों को लगीं। कई मामलों में पुलिसकर्मी घायल भी हुए।

लगभग आधे मामलों में पुलिस ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाया गया और मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार अधिकतर आरोपियों को पैरों या टांगों में गोली मारी गई, वह भी चेतावनी देने के बाद। बरामद हथियार अधिकतर .30 या .32 बोर के बताए गए।

सबसे ज्यादा मुठभेड़ें अमृतसर में हुईं, जहां 9 मामले सामने आए। जबकि, लुधियाना में 5 और पटियाला, बटाला, खन्ना, फिरोजपुर, मोहाली, तरनतारन और जालंधर में दो-दो घटनाएं दर्ज की गईं।

जुलाई 2025 के आधार पर वकील ने किया एनएचआरसी का रुख

जुलाई 2025 में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि साल के पहले सात महीनों में 20 मुठभेड़ें हुईं, जिनमें आरोपी पहले से हिरासत में थे। इन्हीं घटनाओं के आधार पर एक वकील ने एनएचआरसी का रुख किया था।

वकील निखिल सराफ ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, मुठभेड़ में गंभीर चोट लगने पर एफआईआर दर्ज करना और वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराना अनिवार्य है। मौत की स्थिति में मजिस्ट्रेट जांच जरूरी है, लेकिन पंजाब में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा।

Panchjanya, Online News, 20/02/2026

Source: https://panchjanya.com/2026/02/19/458908/bharat/nhrc-action-against-ngo-name-logo-misuse/

नाम और लोगो के दुरुपयोग पर NHRC सख्त, राज्यों को दिए सख्त निर्देश

एजेंसी 19 फ़रवरी 2026

नई दिल्ली (हि.स.) । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है जो आयोग के नाम, लोगो और पदनामों का दुरुपयोग करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सख्त कार्रवाई तथा दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

भ्रामक नामों से जनता को भ्रमित करने का आरोप

आयोग ने गुरुवार को बताया कि कई एनजीओ खुद को राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद जैसे नामों से पंजीकृत करवा रहे हैं, जो सुनने में आधिकारिक वैधानिक निकाय जैसा लगता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये संगठन अध्यक्ष जैसे पदनामों का उपयोग कर जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं। इन भ्रामक नामों के कारण लोग इन्हें आयोग का हिस्सा या उससे मान्यता प्राप्त समझ लेते हैं। इससे न केवल जनता का विश्वास कम हो रहा है बल्कि धन के गबन और जनादेश के दुरुपयोग की भी आशंका है।

दिल्ली में पंजीकरण, कर्नाटक में गतिविधि का मामला

आयोग के अनुसार हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां “राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद” नाम का एक एनजीओ दिल्ली में पंजीकृत पाया गया जबकि वह कर्नाटक में सक्रिय है। इसके प्रचार सामग्री में नीति आयोग और विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध होने के बड़े-बड़े दावे किए गए हैं। इस मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को इस एनजीओ के पंजीकरण और गतिविधियों की जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

सभी राज्यों को नोटिस और सख्त कार्रवाई के निर्देश

इन मामलों के मद्देनजर आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को नोटिस जारी करके निर्देश दिया है कि आयोग के नाम या लोगो का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की तत्काल पहचान की जाए। नियमों का उल्लंघन कर प्राप्त किए गए ऐसे पंजीकरण को तुरंत रद्द किया जाए। दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पंजीकरण अधिकारियों को भविष्य के लिए सतर्क किया जाए।

Dainik Bhaskar, Online News, 20/02/2026

Source:
https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/ambikapur/news/balrampur-hanspur-murder-case-charan-das-mahant-nhrc-137245540.html

हंसपुर हत्याकांड;महंत ने मानवाधिकार आयोग से की जांच की मांग:टीएस सिंहदेव बोले-न्याय में देरी अन्याय के बराबर,अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके बेटे

सरगुजा/बलरापुर 6 घंटे पहले

बलरामपुर के हंसडांड में एसडीएम और गुर्गों की पिटाई से ग्रामीण की मौत के मामले में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को पत्र लिखकर जांच की मांग की है।

नेता प्रतिपक्ष के इस कदम का स्वागत करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर है। मामले में एसडीएम और उनके साथियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है।

रविवार को हंसपुर में बाक्साइट के अवैध उत्खनन के विवाद पर कुसमी एसडीएम करुण डहरिया और गुर्गों ने तीन ग्रामीणों की पिटाई कर दी थी। इनमें एक ग्रामीण राम नरेश उरांव (60 वर्ष) की मौत हो गई थी। दो अन्य घायलों का इलाज कुसमी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। मामले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जांच कमेटी भी बनाई है।

महंत ने मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र लिखा है। महंत ने इस घटना को मानवता पर कलंक बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

डॉ. चरणदास महंत ने अपने पत्र में लिखा है कि हंसपुर गांव में एसडीएम स्तर के अधिकारी द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक निर्दोष बुजुर्ग आदिवासी की मौत हो गई। यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर है।

सिंहदेव बोले-न्याय में देरी अन्याय के बराबर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए नेता प्रतिपक्ष की पहल का स्वागत किया है। सिंहदेव ने कहा है कि बलरामपुर के हंसपुर में आदिवासियों पर हुई बर्बर कार्रवाई और एक व्यक्ति की मौत मूलनिवासियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। अगर प्रशासनिक बल प्रयोग से जान गई है, तो यह सीधी मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

अवैध खनन प्रशासन की शह पर चलने और आदिवासियों पर अत्याचार - ये सब एक ही सिस्टम फेल्योर की कड़ियां हैं। दोषियों की पहचान कर सख़्त से सख़्त सज़ा होनी चाहिए, पीड़ित परिवार के लिए तुरंत न्याय सुनिश्चित किया जाए।

हंसपुर में बाक्साइट के अवैध उत्खनन के मिले सबूत हंसपुर में बड़े पैमाने पर बाक्साइट का अवैध उत्खनन के सबूत मिले हैं। यहां मशीनें लगाकर जंगल में बाक्साइट की अवैध माइनिंग की जा रही थी। इसमें डाल्टेनगंज के राहुल जायसवाल की भूमिका बताई गई है, जिससे एसडीएम का सीधा संपर्क बताया गया है। अवैध उत्खनन का ग्रामीण विरोध कर रहे थे, जो घटना की वजह बना।

पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच सके दो बेटे हंसपुर में मारे गए ग्रामीण राम नरेश उरांव के शव का मंगलवार शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके दो बेटे किशुन राम और संजय बुधवार रात वापस गांव पहुंचे। वे दोनों पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। दोनों छह माह से काम करने चेन्नई गए थे। पिता की हत्या की सूचना पर दोनों वापस लौटे हैं।

मामले की जांच के लिए कांग्रेस की टीम भी गांव में पहुंचेगी। ग्रामीणों ने मामले में संलिप्त अन्य लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

Dainik Bhaskar, Online News, 20/02/2026

Source: https://www.bhaskarhindi.com/city/new-delhi/new-delhi-news-nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-misuse-of-its-name-and-logo-by-ngo-1254663

New Delhi News: एनएचआरसी ने अपने नाम और लोगों का एनजीओ द्वारा दुरुपयोग का लिया स्वतः संज्ञान

19 Feb 2026 5:57 PM

राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

दुरुपयोग का लिया स्वतः संज्ञान

New Delhi News. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने नाम और लोगो (प्रतीक चिन्ह) के गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा दुरुपयोग किए जाने के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को आदेश दिया है कि वे एनएचआरसी के नाम और प्रतीक चिन्ह का दुरुपयोग करने वाले या इससे मिलते-जुलते भ्रामक नामों का उपयोग करने वाले एनजीओ या व्यक्तियों की पहचान कर दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें।

आयोग ने मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को नियमों का उल्लंघन कर प्राप्त किए गए पंजीकरणों को रद्द करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही, पंजीकरण अधिकारियों को सतर्क रहने और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध उचित कदम उठाने को भी कहा गया है। दरअसल, आयोग को देशभर से आम आदमी और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों की जांच करते हुए आयोग ने पाया है कि कई गैर-सरकारी संगठनों ने एनएचआरसी के नाम से मिलते-जुलते भ्रामक नामों से अपना पंजीकरण करा लिया है।

हाल ही में, आयोग को "राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद (एनएचआरसी)" के रूप में पंजीकृत एक एनजीओ के बारे में पता चला, जो कथित तौर पर 2022 में दिल्ली सरकार से पंजीकृत है। आयोग का मानना है कि इस तरह के भ्रामक नामों का जारी रहना जनता के विश्वास को कम कर सकता है और सार्वजनिक अधिकारियों के लिए एनएचआरसी जैसे वैधानिक निकाय और गैर-सरकारी संगठनों के बीच अंतर करने में भ्रम पैदा कर सकता है।

Source: https://khabarchalisa.com/balrampur-hanspur-death-case-nhrc-probe-demand-2026/

HANSPUR DEATH CASE : महंत ने NHRC से जांच मांगी, सिंहदेव बोले – न्याय में देरी अन्याय

By: KC NEWS
Date: February 19, 2026
HANSPUR DEATH CASE : Mahant seeks NHRC probe, Singhdeo says justice delayed is injustice
रायपुर। बलरामपुर जिले के हंसपुर में एसडीएम और कथित गुर्गों की पिटाई से एक ग्रामीण की मौत के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र लिखा है।
महंत ने घटना को "मानवता पर कलंक" बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग से एक बुजुर्ग आदिवासी की मौत होना बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है।
क्या है पूरा मामला?
रविवार को हंसपुर में बाक्साइट के कथित अवैध उत्खनन को लेकर विवाद के दौरान कुसमी एसडीएम करुण डहरिया और उनके साथियों पर तीन ग्रामीणों की पिटाई का आरोप है। इस घटना में 60 वर्षीय राम नरेश उरांव की मौत हो गई, जबकि दो अन्य ग्रामीणों का इलाज कुसमी अस्पताल में चल रहा है।
मामले में एसडीएम और उनके साथियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। जांच के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी एक कमेटी गठित की है।
सिंहदेव का बयान
पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "न्याय में देरी अन्याय के बराबर है।" उन्होंने कहा कि अगर प्रशासनिक बल प्रयोग से किसी की जान गई है तो यह सीधा मानवाधिकार उल्लंघन है। दोषियों को सख्त सजा और पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय मिलना चाहिए।
अवैध खनन के आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि हंसपुर में बड़े पैमाने पर मशीनों के जरिए जंगल क्षेत्र में बाक्साइट का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इस अवैध माइनिंग का ग्रामीण विरोध कर रहे थे, जिसके बाद विवाद बढ़ा। मामले में बाहरी लोगों की संलिप्तता की भी चर्चा है।
अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच सके बेटे
मृतक राम नरेश उरांव का अंतिम संस्कार मंगलवार शाम कर दिया गया। उनके दो बेटे, जो छह महीने से चेन्नई में काम कर रहे थे, सूचना मिलने पर गांव लौटे लेकिन पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके।
गांव में आक्रोश बना हुआ है और ग्रामीणों ने घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Dainik Bhaskar, Online News, 20/02/2026

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/hindi-states-told-to-crack-down-on-imposters-ngos-using-names-identical-to-nhrc-20260219150004-1254622

राज्य एनएचआरसी जैसे नाम इस्तेमाल करने वाले धोखेबाजों और एनजीओ पर कार्रवाई करें

19 Feb 2026 4:53 PM

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (एनएचआरसी) ने गुरुवार को धोखेबाजों और ऐसे एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी, जिन्होंने धोखे से उससे मिलते-जुलते नामों से खुद को रजिस्टर करवाया है। सभी राज्यों को उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

नई दिल्ली, 19 फरवरी (आईएएनएस)। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (एनएचआरसी) ने गुरुवार को धोखेबाजों और ऐसे एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी, जिन्होंने धोखे से उससे मिलते-जुलते नामों से खुद को रजिस्टर करवाया है। सभी राज्यों को उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने एक बयान में कहा कि एनएचआरसी ने सभी राज्यों से दो सप्ताह के अंदर एक्शन-टेकन रिपोर्ट मांगी है। हाल ही में, कमीशन को 'नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल (एनएचआरसी)' के नाम से रजिस्टर्ड एक एनजीओ का पता चला, जो कथित तौर पर 2022 में दिल्ली एनसीटी सरकार के साथ रजिस्टर्ड था, एनएचआरसी ने लोगों से मिली शिकायतों की ओर इशारा करते हुए कहा।

राइट्स पैनल के बयान में कहा गया है कि इस एनजीओ के पब्लिसिटी मटीरियल में दावा किया गया है कि यह नीति आयोग सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है, और आंध्र प्रदेश ह्यूमन राइट्स काउंसिल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है।

एनएचआरसी के बयान में कहा गया है कि उस ऑर्गनाइजेशन से जुड़े एक विजिटिंग कार्ड पर भी 'वेंकटेश, स्टेट चेयरमैन, कर्नाटक' लिखा हुआ है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, उसने मामले का खुद संज्ञान लिया है। उसने कहा कि अपनाया गया नाम और डेजिग्नेशन 'चेयरमैन' गुमराह करने वाला है और कन्फ्यूजन पैदा करता है। इसमें कहा गया है कि गलत नामों से लोगों को यह यकीन हो जाता है कि ये संगठन या तो एनएचआरसी का हिस्सा हैं या ह्यूमन राइट्स के मामलों से निपटने के लिए उससे मान्यता प्राप्त/अधिकृत हैं।

कमीशन का मानना है कि ऐसे गलत नामों के चलते लोगों का भरोसा कम हो सकता है, काम का गलत इस्तेमाल हो सकता है, फंड की हेराफेरी हो सकती है और सरकारी अधिकारियों को एनएचआरसी जैसी कानूनी संस्था और एनजीओ के बीच फर्क करने में कन्फ्यूजन हो सकता है, बयान में कहा गया है।

एनएचआरसी ने कहा कि उसने पहले भी अपने नाम और लोगो के गलत इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर चिंता जताई थी और संबंधित अधिकारियों को ऐसे संदिग्ध संगठनों के पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था।

इसमें कहा गया, 'हालांकि, उल्लंघन हमारे ध्यान में आते रहते हैं।' इसलिए, कमीशन ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी किया है कि वे ऐसे एनजीओ/लोगों की पहचान करें जो एनएचआरसी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या धोखे से मिलते-जुलते नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पर दो सप्ताह के अंदर तुरंत कानूनी कार्रवाई करें, जिसमें नियमों का उल्लंघन करके हासिल किए गए रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना भी शामिल है। उनसे यह भी कहा गया है कि वे रजिस्टरिंग अधिकारियों को सतर्क रहने और डिफॉल्टरों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने के लिए जागरूक करें।

इसके अलावा, एनएचआरसी के इस मामले में, कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस डायरेक्टर जनरल और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को दो सप्ताह के अंदर एनजीओ के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसका ऑफिस कर्नाटक में है और जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है।

Source: https://www.cgmp.co.in/leader-of-opposition-chhattisgarh-assembly-wrote-a-letter-to-nhrc-demanding-independent-investigation-into-tribal-death-in-hanspur-village/149417/

नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा ने NHRC को पत्र लिखकर हंसपुर गांव में आदिवासी मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की

Dipesh Kushwaha | February 19, 2026

रायपुर/बलरामपुर। डॉ.चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) नई दिल्ली को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में एक आदिवासी ग्रामीण की मौत का स्वतंत्र और विस्तृत जांच की मांग की है।

डॉ.चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पत्र लिखकर कहा कि बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में एक जनजातीय ग्रामीण की मौत में स्वतंत्र और विस्तृत पूछताछ के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हंसपुर गांव में हुई एक गहरी दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर घटना पर आकर्षित करना चाहता हूं। बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ जिसने कथित रूप से प्रशासनिक कार्रवाई के कारण एक जनजातीय ग्रामीण की मौत के परिणामस्वरूप किया है। जैसा कि बताया गया है प्रश्न में कार्रवाई में नागरिकों की रक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बल का अत्यधिक उपयोग शामिल था और इसके परिणामस्वरूप निर्दोष जनजातीय निवासी की मौत हो गई। इस घटना ने स्थानीय समुदायों और नागरिक समाज के बीच एकजुट रूप से पीड़ा और संकट उत्पन्न किया है, प्रशासनिक आचरण, जवाबदेही और मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा के बारे में गंभीर प्रश्न उठाए हैं। यदि सत्यापित किया गया है तो इस तरह के कार्यों को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत स्वीकार्य नहीं होगा। मैं दृढ़ता से मानता हूं कि न केवल तथ्यों को स्थापित करने के लिए एक व्यापक, निष्पक्ष, और उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है, बल्कि कानून के शासन में न्याय और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ! 01. सभी भौतिक तथ्यों का पता लगाने के लिए पूरे प्रकरण में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच शुरू करें। 02. जिम्मेदार अधिकारियों या व्यक्तियों की पहचान करें जिनके कार्यों या चूकों ने घटना में योगदान दिया। 03. उचित कानूनी और प्रशासनिक सलाह दें उन सभी के खिलाफ कार्रवाई जो जिम्मेदार पाए गए हैं। 04. पीड़ित के परिवार को तत्काल मुआवजे और समर्थन सुनिश्चित करें। 05. घटना से प्रभावित किसी भी घायलदार ग्रामीणों के लिए उचित उपचार और पुनर्वास सुनिश्चित करें आयोग इस मामले को अत्यंत तत्कालता के साथ मानेंगे अपने मौलिक सार्वजनिक हित और मानवाधिकार संरक्षण के लिए प्रभावों को ध्यान में रखते हुए।

Source: https://smartkhabari.com/threads/9665/

फर्जी NHRC नाम से ठगी पर आयोग सख्त, राज्यों को दो हफ्ते में एक्शन रिपोर्ट देने का फरमान

Thread starter IANS
Start date आज 4:54 PM बजे

नई दिल्ली, 19 फरवरी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (एनएचआरसी) ने गुरुवार को धोखेबाजों और ऐसे एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी, जिन्होंने धोखे से उससे मिलते-जुलते नामों से खुद को रजिस्टर करवाया है। सभी राज्यों को उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि एनएचआरसी ने सभी राज्यों से दो सप्ताह के अंदर एक्शन-टेकन रिपोर्ट मांगी है।
हाल ही में, कमीशन को 'नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल (एनएचआरसी)' के नाम से रजिस्टर्ड एक एनजीओ का पता चला, जो कथित तौर पर 2022 में दिल्ली एनसीटी सरकार के साथ रजिस्टर्ड था, एनएचआरसी ने लोगों से मिली शिकायतों की ओर इशारा करते हुए कहा।
राइट्स पैनल के बयान में कहा गया है कि इस एनजीओ के पब्लिसिटी मटीरियल में दावा किया गया है कि यह नीति आयोग सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है, और आंध्र प्रदेश ह्यूमन राइट्स काउंसिल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है।
एनएचआरसी के बयान में कहा गया है कि उस ऑर्गनाइजेशन से जुड़े एक विजिटिंग कार्ड पर भी 'वेंकटेश, स्टेट चेयरमैन, कर्नाटक' लिखा हुआ है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, उसने मामले का खुद संज्ञान लिया है। उसने कहा कि अपनाया गया नाम और डेजिग्नेशन 'चेयरमैन' गुमराह करने वाला है और कन्फ्यूजन पैदा करता है। इसमें कहा गया है कि गलत नामों से लोगों को यह यकीन हो जाता है कि ये संगठन या तो एनएचआरसी का हिस्सा हैं या ह्यूमन राइट्स के मामलों से निपटने के लिए उससे मान्यता प्राप्त/अधिकृत हैं।
कमीशन का मानना है कि ऐसे गलत नामों के चलते लोगों का भरोसा कम हो सकता है, काम का गलत इस्तेमाल हो सकता है, फंड की हेराफेरी हो सकती है और सरकारी अधिकारियों को एनएचआरसी जैसी कानूनी संस्था और एनजीओ के बीच फर्क करने में कन्फ्यूजन हो सकता है, बयान में कहा गया है।

एनएचआरसी ने कहा कि उसने पहले भी अपने नाम और लोगो के गलत इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर चिंता जताई थी और संबंधित अधिकारियों को ऐसे संदिग्ध संगठनों के पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था।
इसमें कहा गया, 'हालांकि, उल्लंघन हमारे ध्यान में आते रहते हैं।' इसलिए, कमीशन ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी किया है कि वे ऐसे एनजीओ/लोगों की पहचान करें जो एनएचआरसी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या धोखे से मिलते-जुलते नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पर दो सप्ताह के अंदर तुरंत कानूनी कार्रवाई करें, जिसमें नियमों का उल्लंघन करके हासिल किए गए रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना भी शामिल है।
उनसे यह भी कहा गया है कि वे रजिस्टरिंग अधिकारियों को सतर्क रहने और डिफॉल्टरों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने के लिए जागरूक करें।
इसके अलावा, एनएचआरसी के इस मामले में, कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस डायरेक्टर जनरल और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को दो सप्ताह के अंदर एनजीओ के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसका ऑफिस कर्नाटक में है और जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है।

Source: https://thebharatnow.in/chhattisgarh/charandas-mahant-wrote-to-the-national-human-rights-commission-regarding-the-death-of-an-elderly-man-in-balrampur-accusing-the-sdm-of-murder/

बलरामपुर में बुजुर्ग की मौत को लेकर चरणदास महंत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र, SDM पर हत्या का आरोप

छत्तीसगढ़ | February 19, 2026 | Updated: February 19, 2026
By Pradesh Live

CG News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 16 फरवरी को कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई थी. इस मारपीट के कारण एक बुजुर्ग की मौत हो गई. आरोप है कि SDM द्वारा ग्रामीणों से मारपीट की गई थी. अब इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए उन्होंने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

जांच के लिए चरणदास महंत ने लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में एक बुजुर्ग आदिवासी की मृत्यु के मामले में हस्तक्षेप किया है. उन्होंने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र लिखा है. उन्होंने इस घटना को मानवता पर कलंक बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

डॉ. चरणदास महंत ने अपने पत्र में लिखा है कि हंसपुर गांव में SDM स्तर के अधिकारी द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक निर्दोष बुजुर्ग आदिवासी की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर हुई इस घटना ने प्रशासनिक जवाबदेही और आदिवासी समुदाय के मौलिक अधिकारों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला 16 फरवरी 2026 का है. बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में SDM करुण कुमार डहरिया और उनकी टीम अवैध उत्खनन रोकने के लिए पहुंची थे. आरोप है कि इस दौरान SDM करुण और उनकी टीम ने बिना कोई पूछताछ किए सीधे ग्रामीणों मारपीट शुरू कर दी. SDM करुण डहरिया पर 3 ग्रामीणों के साथ मारपीट के आरोप हैं. इनमें से एक ग्रामीण की मौत हो गई. इस पूरे मामले में SDM करुण डहरिया को निलंबित भी कर दिया गया है.

Source: https://www.jansatta.com/jansatta-special/exclusive-investigation-punjab-police-conducted-34-encounters-in-three-months-one-third-died-in-custody/4416061/lite/

पड़ताल: पंजाब पुलिस ने तीन महीने में किए 34 एनकाउंटर, एक तिहाई कस्टडी में मरे

पंजाब पुलिस का तर्क रहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई। कई मामलों में आरोपियों को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था और उसी दौरान मुठभेड़ हुई।
Written by कमलदीप बरार Edited by Sudhanshu Maheshwari
नई दिल्ली | Updated: February 19, 2026 13:08 IST
पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान पुलिस द्वारा कई एनकाउंटर किए गए हैं। आंकड़े इस बात की तस्वीर पेश करते हैं। बड़ी बात यह है कि ज्यादातर एनकाउंटर पुलिस कस्टडी के दौरान हुए हैं। पिछले साल नवंबर में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा था कि अप्रैल 2022 से अब तक राज्य पुलिस द्वारा 324 एनकाउंटर किए गए हैं। इनमें 24 लोगों की मौत हुई है और 515 को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी ने यह भी बताया था कि गिरफ्तार किए गए 515 गैंगस्टरों में से 319 को गोली लगी थी।
यह बयान उस समय आया था जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन (NHRC) ने पंजाब की गृह सचिव को नोटिस भेजा था। आरोप लगाए गए थे कि राज्य में "स्टेट सैंक्शनड एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग" हो रही है।
अब डीजीपी की ओर से आंकड़े पेश कर दिए गए, लेकिन एनकाउंटर की घटनाओं में कमी नहीं दिखी। पिछले तीन महीनों के आंकड़े बताते हैं कि पंजाब पुलिस ने लगभग हर तीसरे दिन एक एनकाउंटर किया। तीन महीनों में कुल 34 एनकाउंटर हुए, जिनमें 5 मौतें हुईं और 45 लोग घायल हुए। इंडियन एक्सप्रेस ने पंजाब सरकार, गृह विभाग और पुलिस को विस्तृत प्रश्न भेजे थे, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।
एनकाउंटर का पैटर्न
अधिकांश मामलों में पुलिस का तर्क रहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई। कई मामलों में आरोपियों को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था और उसी दौरान मुठभेड़ हुई। 8 मामलों में पुलिस पर भी फायरिंग हुई, लेकिन पुलिसकर्मी बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण बच गए। पुलिस का कहना है कि गोली केवल पैरों पर चलाई जा रही है। जिलेवार स्थिति की बात करें तो भटिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, होशियारपुर और फाजिल्का में एक-एक मामला सामने आया। पटियाला, बटाला, खन्ना, फिरोजपुर, मोहाली, तरनतारन और जालंधर में दो-दो मामले दर्ज हुए। लुधियाना में पांच मामले सामने आए। अमृतसर में भी कई केस दर्ज किए गए। 2024 में पंजाब पुलिस ने 64 एनकाउंटर किए। इनमें 4 मौतें हुईं और एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ। 56 आरोपी और 9 पुलिस अधिकारी घायल हुए।

प्रमुख एनकाउंटर की लिस्ट
11 नवंबर
आरोपी हरकरण सिंह और गुरतेज सिंह एक हत्या में शामिल थे। खन्ना पुलिस के साथ उनका एनकाउंटर हुआ। एसएसपी ज्योति यादव के अनुसार, हरकरण ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर घायल हुआ। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और हरकरण के पैर में गोली लगी। गुरतेज सिंह इमारत की पहली मंजिल से कूद गया, जिससे वह घायल हो गया।
12 नवंबर
डेरा बस्सी में गोल्डी ढिल्लों गैंग के सदस्य शरणजीत सिंह और अमन कुमार के साथ मुठभेड़ हुई। एसएसपी हरमंदीप हंस के अनुसार, दोनों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने फायरिंग की और दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी।
15 नवंबर
फरीदकोट पुलिस ने प्रभ दसुवाल गैंग के अर्शदीप सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। नाकाबंदी के दौरान उसने पुलिस टीम पर हमला किया। जवाबी फायरिंग में वह घायल हुआ और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
4 दिसंबर
शूटर दलेर सिंह का एनकाउंटर पुलिस कस्टडी के दौरान हुआ। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के अनुसार, उसे रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। उसने अचानक हथियार निकालकर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी।
6 दिसंबर
श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने किडनैपिंग और नाबालिग हत्या मामले में मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली भी चलाई। उसके बाद मुठभेड़ हुई और उसे गोली लगी।
15 दिसंबर

अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने वंशप्रीत सिंह और भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा था कि दोनों लंबे समय से एक्सटॉर्शन और लूट के मामलों में शामिल थे। मुठभेड़ के दौरान फायरिंग हुई।

27 दिसंबर

राजगढ़ गांव में आरोपी इंद्रजीत सिंह और गुरवीर सिंह ने सरपंच पर गोली चलाई थी। एसएसपी ज्योति यादव के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान इंद्रजीत ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी।

6 जनवरी

तरनतारन जिले में गैंगस्टर प्रभ दासुवाल और अफरीदी का करीबी हरनौर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। डीआईजी बॉर्डर रेंज के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि नूर बाइक से आ रहा है। ऐसे में पुलिस ने उसका पीछा किया और आरोपी ने गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई। उसी मुठभेड़ में उसकी मौत हुई।

7 जनवरी

अमृतसर में गुरपीत सिंह लाल वेपन रिकवरी के दौरान भागने की कोशिश में घायल हुआ। पुलिस के अनुसार, उसने गोली चलाई और जवाबी फायरिंग में जख्मी हुआ। इसके अलावा 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 और 29 जनवरी को भी कई एनकाउंटर हुए। लगभग सभी मामलों में एक समान पैटर्न देखने को मिला- या तो आरोपी ने भागने की कोशिश की या दावा किया गया कि पहले गोली आरोपी ने चलाई।

एडवोकेट निखिल सराफ ने इन कथित फर्जी एनकाउंटर मामलों को गंभीरता से उठाया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हर ऐसे एनकाउंटर में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जहां आरोपी गंभीर रूप से घायल होता है। यदि किसी की मौत होती है तो मजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य है। वरिष्ठ अधिवक्ता सरबजीत सिंह भी 1990 के दशक से ऐसे मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे एनकाउंटर स्पष्ट लगे, जांच होना आवश्यक है और न्यायपालिका को स्वत: ऐसे मामलों का संज्ञान लेना चाहिए।

Univarta, Online News, 20/02/2026

Source: https://www.univarta.com/story/India/news/3746419.html

एनएचआरसी ने अपने नाम और लोगो के एनजीओ द्वारा दुरुपयोग का स्वतः संज्ञान लिया

Uniindia News Service | भारत Posted at: Feb 19 2026 4:04PM

नयी दिल्ली, 19 फरवरी (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने नाम और लोगो के गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा दुरुपयोग का स्वतः संज्ञान लिया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आज बताया कि आयोग को देशभर के व्यक्तियों और एनजीओ से मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों की जांच करते हुए आयोग ने पाया है कि कई गैर-सरकारी संगठनों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से मिलते-जुलते भ्रामक नामों से अपना पंजीकरण करा लिया है।

विस्तृत समाचार के लिए हमारी सेवाएं लें।.

Source: https://www.yugwarta.com/Encyc/2026/2/19/NHRC-NGO-DGP-NOTICE-DELHI-PUNJAB.amp.html

नाम, लोगो का दुरुपयोग करने वाले एनजीओ पर सख्ती, मानवाधिकार आयोग का राज्यों को नोटिस

19 Feb 2026 15:47:53

नई दिल्ली, 19 फरवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है जो आयोग के नाम, लोगो और पदनामों का दुरुपयोग करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सख्त कार्रवाई तथा दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

आयोग ने गुरुवार को बताया कि कई एनजीओ खुद को राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद जैसे नामों से पंजीकृत करवा रहे हैं, जो सुनने में आधिकारिक वैधानिक निकाय जैसा लगता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये संगठन अध्यक्ष जैसे पदनामों का उपयोग कर जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं। इन भ्रामक नामों के कारण लोग इन्हें आयोग का हिस्सा या उससे मान्यता प्राप्त समझ लेते हैं। इससे न केवल जनता का विश्वास कम हो रहा है बल्कि धन के गबन और जनादेश के दुरुपयोग की भी आशंका है।

आयोग के अनुसार हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद नाम का एक एनजीओ दिल्ली में पंजीकृत पाया गया जबकि वह कर्नाटक में सक्रिय है। इसके प्रचार सामग्री में नीति आयोग और विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध होने के बड़े-बड़े दावे किए गए हैं। इस मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को इस एनजीओ के पंजीकरण और गतिविधियों की जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

इन मामलों के मद्देनजर आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को नोटिस जारी करके निर्देश दिया है कि आयोग के नाम या लोगो का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की तत्काल पहचान की जाए। नियमों का उल्लंघन कर प्राप्त किए गए ऐसे पंजीकरण को तुरंत रद्द किया जाए। दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और पंजीकरण अधिकारियों को भविष्य के लिए सतर्क किया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी

Source: https://www.jagran.com/haryana/faridabad-surajkund-swing-accident-human-rights-commission-seeks-report-40147388.html?utm_source=article_detail&utm_medium=CRE&utm_campaign=latestnews_CRE

सूरजकुंड झूला हादसा: मानव आयोग ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट, सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस नीति का निर्देश

By Nibha Rajak Edited By: Rajesh Kumar
Updated: Thu, 19 Feb 2026 03:35 PM (IST)

मानव अधिकार आयोग ने 7 फरवरी को सूरजकुंड मेले में हुए झूले हादसे का संज्ञान लिया है। आयोग ने फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर आयुष सिन्हा से एक महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में जांच के नतीजे, FIR की स्थिति और आरोपियों पर कार्रवाई शामिल होनी चाहिए। आयोग ने शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के परिवार को मुआवजे और सार्वजनिक आयोजनों में पुलिस सुरक्षा पर भी रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने मेले में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी पर चिंता जताई है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 39वें सूरजकुंड इंटरनेशनल सेल्फ-रिलायंट क्राफ्ट्स मेले में 7 फरवरी को हुए झूले हादसे का संज्ञान लिया है और अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर आयुष सिन्हा को एक महीने के अंदर एक डिटेल्ड रिपोर्ट देने को कहा गया है, जिसमें जांच कमिटी के नतीजे, FIR का मौजूदा स्टेटस और आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई शामिल हो।

शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के परिवार को दिए गए मुआवजे और पब्लिक इवेंट्स में तैनात पुलिसवालों की सुरक्षा पक्का करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी रिपोर्ट मांगी गई है।

कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा, कुलदीप जैन और दीप भाटिया ने बताया कि सुनामी झूला, जो लगभग 26 लोगों के साथ पूरी कैपेसिटी से चल रहा था, अचानक गिर गया। हादसे में 13 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जबकि इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ने दूसरों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी।

हरियाणा सरकार, हेरिटेज और टूरिज्म डिपार्टमेंट और सूरजकुंड मेला अथॉरिटी को मेलों और अम्यूजमेंट राइड्स के लिए मौजूदा सेफ्टी गाइडलाइंस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट देने और उन्हें मजबूत करने के लिए सुझाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा गया है।

एक ही दिन में दो घटनाएं

घटना वाले दिन, कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ललित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया, और रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) संजय कुमार खंडूजा मेले में कमीशन के अवेयरनेस कैंप में मौजूद थे। दोपहर में, तेज हवाओं के कारण फूड कोर्ट एरिया के पास एक टेम्पररी एंट्रेंस गेट गिर गया, जिससे दो-तीन लोग घायल हो गए। इसके तुरंत बाद, एक झूले के गिरने की खबर मिली। कमीशन ने कहा कि मेले में लगाए गए एंट्रेंस गेट, स्टॉल और मनोरंजन की सवारी टेम्पररी और नाजुक थीं। यह गंभीर लापरवाही दिखाता है।

कमीशन का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का निर्देश

सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेले में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कमीशन ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को पब्लिक सेफ्टी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का निर्देश दिया है। साथ ही, मल्टी-डिसिप्लिनरी टेक्निकल कमेटी (स्ट्रक्चरल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक्सपर्ट, फायर ऑफिसर और डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर) से पहले सर्टिफिकेशन के बिना मेला शुरू न करने और सभी झूलों, एंट्रेंस गेट, स्टॉल और टेम्पररी स्ट्रक्चर का सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं।

वेन्यू पर काफी संख्या में इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, एम्बुलेंस, फायर व्हीकल, फर्स्ट एड स्टेशन और ट्रेंड रेस्क्यू स्टाफ तैनात करने और सेफ्टी स्टैंडर्ड के उल्लंघन के मामले में ऑर्गनाइजर और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सज़ा देने वाली और डिसिप्लिनरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

Source:
https://www.univarta.com/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%8F%E0%A4%9A%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%B8-%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%A8-%E0%A4%9F%E0%A4%95-%E0%A4%AC-%E0%A4%B8-%E0%A4%AB-%E0%A4%9F-%E0%A4%AE-%E0%A4%A6-%E0%A4%B2-%E0%A4%97-%E0%A4%95-%E0%A4%AE-%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8-%E0%A4%B5%E0%A4%A4-%E0%A4%B8-%E0%A4%9C-%E0%A4%9E-%E0%A4%A8-%E0%A4%B2-%E0%A4%AF/india/news/3746554.html

एनएचआरसी ने कर्नाटक बिस्फोट में दो लोगों की मौत पर स्वत: संज्ञान लिया

Uniindia News Service | भारत Posted at: Feb 19 2026 5:06PM
नयी दिल्ली 19 फरवरी (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कर्नाटक में मांड्या जिले के बसारालू इलाके में एक रसायन प्लांट में हुए विस्फोट से दो लोगों की मौत और चार अन्य के गंभीर रूप से घायल होने का स्वत: संज्ञान लिया और राज्य के मुख्य सचिव एवं मांड्या के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
एनएचआरसी ने आज बताया कि आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि 15 फरवरी को कर्नाटक के मांड्या जिले के बसारालू इलाके में एक केमिकल प्लांट में हुए बिस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रिपोर्ट में स्थानीय लोगों ने कहा कि बिस्फोट लापरवाही के कारण हुआ क्योंकि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।
विस्तृत समाचार के लिए हमारी सेवाएं लें।.

Source: https://aajkijandhara.com/urban-administration-cracks-down-orders-for-the-third-time-prohibit-family-members-from-interfering-in-the-work-of-women-public-representatives/

नगरीय प्रशासन की सख्ती : महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज में परिजनों के दखल पर तीसरी बार रोक के आदेश

Uma Baghel | February 19, 2026

आदेश के बावजूद अधिकारियों द्वारा गंभीरतापूर्वक कार्यवाही नहीं की जा रही

सरकार व सत्ताधारी पार्टी का दबाव आदेश के पालन में अड़चन

दिलीप गुप्ता

सरायपाली : महिलाओं के सशक्तिकरण व उनको राजनीतिक रूप से मजबूत किये जाने वी उनके कार्यों में उनके परिजनों के हस्तक्षेप को रोके जाने हेतु नगरीय प्रशासन द्वारा तीसरी बार आदेश जारी किया गया है । यह आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप व आदेश पुनः जारी किया गया । संचनालय द्वारा एक ही विषय को लेकर तीसरी बार आदेश जारी किया जाना ही यह दर्शाता है कि संबंधित अधिकारियों व विभाग द्वारा जारी आदेश को मूल भावनाओं के अनुरूप आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है ।यह कृत्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ ही अपने उच्च अधिकारियों के आदेश व निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना भी है जो एक गंभीर व चिंताजनक भी है ।

देश में आधी आबादी के नाम से पहचाने जाने वाली महिला आबादी को सक्रिय राजनीति , सामाजिक व अन्य गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाये जाने हेतु आरक्षण की सुविधाएं भी प्रदान की गई है ताकि वे प्रत्येक क्षेत्र में खासकर चुने हुवे जनप्रतिनिधियों के रूप में अपने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सक्रिय भागीदारी निभा सके । जिससे उनके सक्रियता से वे अनुभव व कार्य किए जाने की क्षमता के साथ साथ मानसिक, सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्र में पहचान बना कर अपने अपने क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास भी कर सके । पुरुषों के साथ वे कंधे से कंधे मिलकर बराबर चल सकें । किंतु सरकार व महिलाओं की इस भावनाओं व उद्देश्यों को स्वयं चुने हुवे महिलाएं , महिलाओं के परिजन व संबंधित अधिकारियों द्वारा ही पलीता लगाया जा रहा है जिससे सरकार के महिला सशक्तीकरण की भावनाओं को आघात लग रहा है ।

इस संबंध में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा क्र./शा-1/विविध/7062/2025/12541 दिनांक 3-2-26 को पुनः एक पत्र राज्य के समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम व समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत को पत्र जारी करते हुवे कहा गया है कि नगरी निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पारिवारिक रिश्तेदार /नातेदार को प्रॉक्सी प्रतिनिधि/लायज़न पर्सन के नियुक्ति पर रोक के संबंध में शासन के पत्र क्र. VIGI-2904/2/2025-UAD दिनांक 12.12.2025 के तहत समस्त नगरीय निकायों को निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पारिवारिक रिश्तेदार / नातेदार को प्रॉक्सी प्रतिनिधि/लायज़न पर्सन के नियुक्ति पर रोक हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त संबंध में अपने निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पारिवारिक रिश्तेदार/नातेदार जो नामांकित जनप्रतिनिधि हैं, के संबंध में जानकारी निर्धारित प्रपत्र-01 में अविलंब क्षेत्रीय संयुक्त संचालक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है ।

ज्ञातव्य हो कि प्रपत्र 01 एक तह का प्रोफार्मा होता है जो पत्र के साथ संलग्न किया जाता है । इस पत्र में संबंधित महिला जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदारों / नातेदारों व परिजनों के नामों की जानकारी दी जानी होती है ताकि सरकार व विभागों के पास उनकी जानकारी उपलब्ध हो सके ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा महिलाओं के कार्यों में उनके पति , पुत्र व अन्य परिजनों द्वारा लगातार किए जा रहे हस्तक्षेप को संज्ञान में लेते हुवे सरकारवको इसे रोके जाने हेतु आदेशित किया गया था। सरकार व संचनालय द्वारा पूर्व में इस संबंध में पहली बार पत्र क्रमांक 4426/3946/18/2010 दिनांक 20/08/2010 तथा viji 2904/2/2025/UAD दिनांक 12/12/2025 के तहत दो बार इस दूषित प्रॉक्सी प्रचलन को रोके जाने हेतु आदेश जारी किया गया था । संचनालय द्वारा विगत 13/2/2026 को पुनः तीसरी बार आदेश जारी करने के पीछे यह स्पष्ट उद्देश्य है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिये गये विभागीय आदेशों व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का शब्दशः पालन नहीं किया गया । अब अभी कुछ दिनों पूर्व किए गये आदेश का पालन किया जायेगा या होगा इसकी कोई गारंटी विभाग या सरकार लेगी यह आने वाला समय बतायेगा ।

ज्ञातव्य हो कि आज भी सरायपाली के अनुविभागीय क्षेत्र में नगरपालिका , ग्रामपंचायतों , जनपद पंचायतों व जिला जनपद में चुने हुवे महिला जनप्रतिनिधियों को स्थानीय स्तर पर आयोजित शासकीय , सामाजिक , धार्मिक , खेलकूद , सांस्कृतिक कार्यक्रमों , बैठकों व अन्य गतिविधियों में नाम तो इन महिलाओ का होता है पर कार्यक्रमों में महिलाओं के स्थान पर उनके पति , पुत्र व अन्य परिजन " प्रतिनिधि " के रूप में शामिल होते हैं । कार्यक्रमों में उनका सम्मान , स्वागत , भाषण भी इसी नाम से किया जाता है । अभी एक विभाग द्वारा संभागीय स्तर पर विभिन्न स्थानों पर रजत जयंती के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था जिनमें अधिकांश कार्यक्रमों में यही लोग " प्रतिनिधि " के रूप में शामिल हुवे थे । यहां तक कि उनकी वाहनों , नेम प्लेटो , बैनरों , फ्लेक्सो , आमंत्रण , निमंत्रण पत्रों व अखबारों में आने वाले विज्ञापनों में भी संबंधित महिलाओं के "प्रतिनिधि " के रूप में इनका नाम प्रकाशित होते दिखाई देता है । स्वयं महिलाएं ऐसे कार्यक्रमों में न आती हैं न उन्हें आने दिया जाता है । ऐसे में महिला सशक्तीकरण का उद्देश्य कैसे सफल होगा । सबसे गंभीर सवाल यह है कि 2-2 बार इस प्रक्रिया को रोके जाने हेतु आदेश पारित किये जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा इसे गंभीरता से रोक न लगाकर स्वयं लगातार

गलती कर रहे हैं । विभिन्न विभागो द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में स्वयं इन प्रतिनिधियों पर रोक लगाए जाने के स्थान पर उनका बाकायदा स्वागत , सत्कार , भाषण ,सम्मान आदि किया जाता है । जब अधिकारियों द्वारा ही शासकीय आदेशों की धज्जियां उड़ाई जायेगी तो कथित प्रॉक्सी/ लायजन पर्सन/पति /पुत्र/ नातेदार /रिश्तेदार प्रतिनिधियों पर शासन के मंशानुसार रोक कैसे लग पाएगी व निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का मान , सम्मान , अनुभव , सक्रियता व महिला सशक्तीकरण का उद्देश्य कैसे सफल हो पायेगा।

Source: https://hindi.livelaw.in/amp/jharkhand-high-court/justice-ms-sonak-justice-rajesh-shankar-section-176-1a-of-crpc-judicial-inquiry-judicial-custody-custodial-rape-custodial-death-523791

हिरासत में 437 मौतों पर झारखंड हाइकोर्ट सख्त, मजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य, राज्य से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

By - Amir Ahmad | Update: 2026-02-19 09:00 GMT

झारखंड हाइकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 176(1-क) (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 196) के तहत पुलिस या न्यायिक हिरासत में मृत्यु, लापता होने या दुष्कर्म के हर मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक जांच अनिवार्य है। अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी, क्योंकि राज्य ने खुलासा किया कि वर्ष 2018 से 2025 के बीच 437 लोगों की हिरासत में मौत हुई।

चीफ जस्टिस एम. एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई कि हिरासत में मृत्यु लापता होने या दुष्कर्म के सभी मामलों में न्यायिक जांच की वैधानिक अनिवार्यता का पालन सुनिश्चित किया जाए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल द्वारा दायर शपथपत्र का उल्लेख किया। शपथपत्र के साथ तालिका संलग्न थी, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2018 से 2025 के बीच 437 व्यक्तियों की पुलिस या न्यायिक हिरासत में मृत्यु हुई। हालांकि तालिका में यह उल्लेख था कि मृत्यु की सूचना मजिस्ट्रेट को दी गई या नहीं लेकिन अधिकांश मामलों में यह स्पष्ट नहीं था कि धारा 176(1-क) के तहत अनिवार्य न्यायिक जांच वास्तव में कराई गई या नहीं।

अदालत ने कहा कि यह मामला काफी समय से लंबित है और पहले भी राज्य को कई अवसर दिए जा चुके हैं कि वह वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित पूरी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से दे।

प्रावधान के उद्देश्य पर जोर देते हुए पीठ ने कहा कि धारा 176(1-क) स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करती है कि पुलिस जांच के अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतंत्र न्यायिक जांच भी की जाए ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,

“इन 437 मौतों के संबंध में क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कोई जांच की गई, यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम झारखंड सरकार के गृह सचिव को निर्देश देते हैं कि वे इस संबंध में शपथपत्र दाखिल करें। यदि पुलिस जांच के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई तो ऐसे मामलों का विवरण भी शपथपत्र में दिया जाए। शपथपत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति भी स्पष्ट की जाए क्योंकि उपलब्ध आंकड़ों में वर्ष 2023 से 2025 तक की हिरासत मौतें भी शामिल हैं।”

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य द्वारा दायर किए जाने वाले शपथपत्र में यह स्पष्ट किया जाए कि हिरासत में मौत के मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया या नहीं।

खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान शपथपत्र और तालिका से यह स्पष्ट नहीं है कि मृत्यु के कारण का निर्धारण केवल पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया या कानून के तहत अनिवार्य स्वतंत्र न्यायिक जांच भी कराई गई। अदालत ने कहा कि हिरासत में बड़ी संख्या में हुई मौतों को देखते हुए यह आवश्यक है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को समाप्त करने के लिए बनाए गए वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन हुआ या नहीं।

अदालत ने झारखंड सरकार के गृह सचिव को 13 मार्च, 2026 तक विस्तृत और समग्र शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को निर्धारित की गई।

Source: https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-nhrc-acts-against-ngos-misusing-name-logo-across-states-40147949.html

फर्जी 'NHRC' संगठनों पर आयोग का स्वतः संज्ञान, नाम और लोगो के दुरुपयोग पर सभी राज्यों को भेजा नोटिस

By Ritika Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Thu, 19 Feb 2026 11:05 PM (IST)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने अपने नाम और लोगो का दुरुपयोग करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे भ्रामक संगठनों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

HighLights

NHRC ने नाम और लोगो के दुरुपयोग पर स्वतः संज्ञान लिया।
सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश।
दिल्ली में फर्जी 'नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल' पर कार्रवाई शुरू।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने नाम और लोगो का दुरुपयोग करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ स्वत संज्ञान लेते हुए देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि उसके नाम से मिलते-जुलते भ्रामक संगठनों की गतिविधियां जारी रहना सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है।

दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

हाल ही में आयोग के संज्ञान में नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल (एनएचआरसी) नाम से एक एनजीओ आया, जो वर्ष 2022 में दिल्ली में पंजीकृत हुआ था और अपने प्रचार सामग्री में विभिन्न सरकारी संस्थाओं से संबद्ध होने का दावा कर रहा था। संगठन के विजिटिंग कार्ड पर प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदनाम भी दर्शाए गए, जिसे आयोग ने भ्रामक बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

पंजीकरण प्राधिकरणों को सतर्क करने का निर्देश

इसके साथ आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर ऐसे संगठनों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने, आवश्यक होने पर उनका पंजीकरण रद करने और संबंधित पंजीकरण प्राधिकरणों को सतर्क करने का निर्देश दिया है।

विश्वसनीयता पर असर पड़ने का खतरा

एनएचआरसी ने पाया कि कई एनजीओ स्वयं को ऐसे नामों से पंजीकृत करा रहे हैं जो आयोग के नाम से बेहद मिलते-जुलते हैं, जिससे आम जनता और सरकारी एजेंसियों में भ्रम पैदा होता है। आयोग के अनुसार इससे उसके अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग, फंड के संभावित दुरुपयोग और संस्थागत विश्वसनीयता पर असर पड़ने का खतरा है।

आयोग ने कहा कि पहले भी संबंधित प्राधिकरणों को ऐसे फर्जी या भ्रामक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगाह किया गया था, लेकिन उल्लंघन जारी रहने के कारण अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।